<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 6/34/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 23.09.2025

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं.-पाटनरोधी (ओआई)-32/202</u>

<u>विषय: कुवैत सरकार, सऊदी अरब साम्राज्य और सिंगापुर गणराज्य के मूल के अथवां वहां से निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।</u>

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

फा. सं. 6/34/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि, दि केमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीपीएमए) (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों की पहचान, आकलन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष कुवैत सरकार (जिसे आगे 'एसओके/कुवैत' भी कहा गया है), सऊदी अरब साम्राज्य (जिस यहां आगे 'केएसए/सऊदी अरब" भी कहा गया है) और सिंगापुर गणराज्य (जिसे यहां आगे

'आरओएस/सिंगापुर' भी कहा गया है), जिन्हें यहां आगे सामूहिक रूप से "संबद्ध देश" कहा गया है, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल" (जिसे यहां आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध सामान' अथवा 'एमईजी' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया है। क्षति संबंधी सूचना से संबंधित आंकड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक कंपनी", "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा दिए गए थे।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/34/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2024 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जरी की, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई है ताकि संबद्ध सामानों के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश की जा सके।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या फा.सं.6/34/2024 - डीजीटीआर द्वारा 27 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु की गई।

ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच

शुरु किए जाने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार देने का अनुरोध किया।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहाँ भी अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराई गई थी।

ड. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एक निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

एसओके	**केएसए**	**आरओएस**
इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी	अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	कोरल एनर्जी डीएमसीसी
दि कुवैत ओलेफिन्स कंपनी	ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	शेल इंटरनेशनल ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी
	जना जुबैल केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी	
	रबीघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	
	सदारा केमिकल कंपनी	
	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन	
	सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी	
	सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी	
	यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी	

च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

छ. प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

क्र.सं.	**एसओके**	**केएसए**	**आरओएस**
उत्पादक			
1.	इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी ("इक्वेट")	सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानपेट")	-
2.	कुवैत ओलेफिन्स कंपनी ("टीकेओसी")	सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी ("सऊदी कायान")	
3.		जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यूनाइटेड")	
4.		ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी ("शार्क")	
5.		अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पेट्रोकेमा")	
6.		यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("यानसब")	
7.		रबीघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी ("पीआरसी")	

व्यापारी			
8.		मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, जापानसऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ("एसएबीआईसी")	
9.		एसपीडीसी लिमिटेड ("एसपीडीसी")	
10.		एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड ("एसएपीपीएल")	
11.	मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान	मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान	

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन का नाम
1.	डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
3.	भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4.	चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड
5.	डीएनएच स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	जिंदल पॉली फिल्म्स
7.	श्री दुर्गा सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	सनाथन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड
10.	शुभलक्ष्मी पॉलिएस्टर्स लिमिटेड

11.	एसआरएफ लिमिटेड
12.	स्टार्चेम पॉलीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
13.	स्टारलॉन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
14.	द बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
15.	वेलनोउन पॉलिएस्टर्स लिमिटेड
16.	इंडोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड
17.	आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
18.	गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड
19.	गोकुलानंद पेट्रोफाइबर्स
20.	जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
21.	सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड
22.	रश्मि पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड
23.	आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
24.	फ्यूचरा पॉलिएस्टर्स लिमिटेड

झ. प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर उत्तर दिया है:

क्र.सं.	**आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन का नाम**
1.	भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	मेसर्स आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3.	सनाथन टेक्सटाइल्स लिमिटेड
4.	बीकेलॉन सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	डी.एन.एच. स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	गार्डन सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	वेलनोन पॉलिएस्टर्स लिमिटेड
8.	बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
9.	मेसर्स फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
10.	मेसर्स इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड

11.	पॉलिएस्टर टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

ञ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ट. डीजीसीआईएंडएस से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जांच के बाद आयात की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ठ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ड. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्यों द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर देने का निर्देश दिया गया था।

ण. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

त. प्राधिकारी ने 27 सितंबर 2024 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 6 के द्वारा जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में टिप्पणियां मांगी। हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) पद्धति के संबंध में टिप्पणियाँ दायर करने के लिए 26 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया गया। चूँकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध दायर नहीं किया गया था, अत: प्राधिकारी ने 18 नवंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के अंतिम क्षेत्र और पीसीएन को अधिसूचित किया। सभी हितबद्ध पक्षकरों को 18 दिसंबर 2024 तक अंतिम रूप से तैयार विचाराधीन उत्पाद के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर दायर करने का निर्देश दिया गया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, समय सीमा को आगे बढ़ाकर 25 दिसंबर 2024 कर दिया गया।

थ. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के निर्माण और बिक्री की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

द. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 17 अप्रैल 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और उनसे लिखित और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी में

परिवर्तन के कारण, प्राधिकारी ने ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 07-01-2011 को सिविल अपील संख्या 949/2006 में दिए गए निर्णय के अनुसरण में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने और उसके बाद लिखित रूप में अनुरोध देने का अवसर प्रदान किया। तदनुसार, प्राधिकारी ने 4 जून, 2025 को एक और सार्वजनिक सुनवाई की। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने दूसरी मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर अनुरोध दें। हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया था।

ध. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को 09 सितंबर 2025 को परिचालित किया। पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, 16 सितंबर 2025 तक दायर करें।

न. प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन-पश्चात सभी टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध, जो केवल पिछले अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

प. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की, जहां तक आवश्यक समझा गया, स्थल-सत्यापन के साथ-साथ तालिका सत्यापन के दौरान जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

फ. संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच और डेस्क सत्यापन भी जहां तक आवश्यक समझा गया, किया

गया और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।

ब. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाते हैं।

भ. अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

म. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डा. =83.70 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

4. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद या पीसीएन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी है।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

5. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद "मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल" है। यह सभी पॉलिएस्टर यार्न, फाइबर और पीईटी के उत्पादन के लिए एक आधारभूत कच्ची सामग्री है। देश में इसकी घरेलू उपलब्धता टेक्सटाइल और पीईटी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

ख. अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्पाद क्षेत्र के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है अथवा पीसीएन के निर्माण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करने का अनुरोध करता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. विचाराधीन उत्पाद 'मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी)' है। एमईजी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र (सीएच2ओएच)2 है। एमईजी की आणविक संरचना इस प्रकार है:

एक बीकर में एमईजी

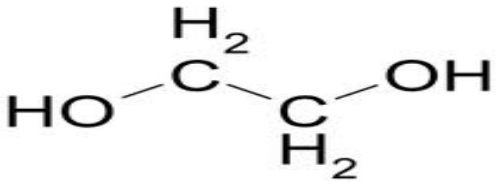

एमईजी की आणविक संरचना

7. एमईजी मुख्यतः दो ग्रेड का होता है - फाइबर और गैर-फाइबर। घरेलू उद्योग एमईजी के दोनों ग्रेड का निर्माण करता है। वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दोनों ग्रेड शामिल हैं।

8. एमईजी एक पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, हल्का चिपचिपा द्रव है जिसकी स्थिरता सिरप जैसी होती है। इसके अतिरिक्त, इसका स्वाद मीठा होता है और यह पानी में घुल जाता है। एमईजी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिसका व्यापक उपयोग होता है। इसका उपयोग मुख्यतः पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन के निर्माण के लिए शुद्ध टेरेफ्थेलिक अम्ल के साथ संयोजन में किया जाता है। इसका उपयोग एंटी-फ्रीज/शीतलक के साथ-साथ फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक उद्योगों में भी किया जाता है।

9. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 2905 31 00 के अंतर्गत "कार्बनिक रसायन" शीर्षक वाले अध्याय 29 में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. वर्तमान जाँच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं दिया। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में कोई पीसीएन पद्धति नहीं

अपनाई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

11. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के आरंभिक चरण में परिभाषित उत्पाद क्षेत्र की पुष्टि करते हैं: "3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी) है।"

12. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और सामानों के बाजार एवं प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में आने वाले संबद्ध सामान, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। सब्सिडी प्राप्त आयातित सामानों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों तथा आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, प्रकार्यों अथवा अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए इन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान मामले में आरआईएल "घरेलू उद्योग" नहीं माना जा सकता क्योंकि परिभाषा में *"समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों, जो समान वस्तु के विनिर्माण में लगे हैं"* की परिकल्पना की गई है, और वर्तमान कार्यवाही में आरआईएल के अलावा कोई अन्य भागीदार नहीं है।

ख. आरआईएल के आंकड़ों पर पूरी तरह निर्भरता क्षति विश्लेषण की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को कमजोर करती है क्योंकि इससे चुनिंदा आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण और संभावित हेरफेर का जोखिम होता है, जिससे क्षति मूल्यांकन की सटीकता और पारदर्शिता से समझौता होता है। अन्य घरेलू उत्पादकों से तुलनीय आंकड़ों के अभाव में, कीमत और लागत आंकड़ों जैसे महत्वपूर्ण क्षति संकेतक सत्यापन योग्य नहीं रहते हैं। इस संबंध में

ईसी - फास्टनर्स (चीन), यूएस - हॉट रोल्ड स्टील (जापान) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट और *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

ग. "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में संबद्ध सामानों के आयातकों को भी शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान कार्यवाही में, आरआईएल संबद्ध देशों से एमईजी का उत्पादक और आयातक दोनों है, जो हितों के टकराव पैदा करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह एकमात्र प्रतिभागी उत्पादक है और उसका घरेलू उत्पादन में 80-90% हिस्सा है।

घ. *सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई) लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग के क्षेत्र में आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों को शामिल करने का विवेकाधिकार पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों की प्रकृति और कारण की जांच करनी चाहिए।

ङ. आवेदक ने दावा किया है कि वर्तमान आवेदन-पत्र को आईओसीएल और आईजीएल का भी समर्थन प्राप्त है। तथापि, आईओसीएल की ओर से इस तरह के कथित समर्थन का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक ने स्वयं अपने आवेदन-पत्र में आईओसीएल को वर्तमान जांच के प्रति तटस्थ माना है।

च. हाल ही में बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आरआईएल ने लगभग 180 किलोटन विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि ऐसे आयात आरआईएल की कुल बिक्री और उत्पादन का केवल 1% कैसे हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान आवेदन-पत्र केमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("आरआईएल") की ओर से दायर किया गया है। आरआईएल का भारतीय उत्पादन में 75% से अधिक हिस्सा है और उसका पाटनरोधी नियमावली,

1995 के नियम 2(ख) के अनुसार भारत में कुल घरेलू उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाएं भी पूरी कर ली गई हैं।

ख. भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य ज्ञात उत्पादक, अर्थात् इंडियन ग्लाइकॉल लिमिटेड और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड हैं।

ग. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का नगण्य मात्रा में आयात किया है। तथापि, ऐसे आयात कुल मांग के 1 प्रतिशत से भी कम और इसके उत्पादन का लगभग 1% हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे आयात निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत किए गए हैं।

घ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में "सकता है" शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से प्राधिकारी को ऐसे घरेलू उत्पादकों को भी शामिल करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जो या तो संबद्ध सामानों के आयातक हैं या फिर ऐसा घरेलू उत्पादक निर्यातक का संबद्ध पक्षकार है।

ड. *ईसी - फास्टनर्स (चीन)* मामले में पैनल ने पाया कि जाँच प्राधिकारियों के पास संबंधित या आयातक घरेलू उत्पादकों को बाहर रखने या न रखने का विवेकाधिकार है। *सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स बनाम भारत संघ* मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी इस विवेकाधिकार की पुष्टि की थी। इसके अतिरिक्त, मेलामाइन और सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने आयातक घरेलू उत्पादक और संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया था।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

'(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन-पत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदन-पत्र का समर्थन इंडियन ग्लाइकॉल लिमिटेड ने किया है। इन दोनों उत्पादकों के अलावा, एक अन्य उत्पादक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, 'प्रमुख अनुपात' है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। तथापि, ऐसे आयात उनके कुल उत्पादन और देश में समग्र माँग का केवल 1% ही हैं। यह सीमित आयात गतिविधि आवेदक के व्यवसाय की प्रकृति को निर्माता से व्यापारी में नहीं बदलती है। तदनुसार, आवेदक वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने का पात्र है। इसके अतिरिक्त, आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

18. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

21. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों के मुद्दे उठाए हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की

गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फ़ाइल के रूप में उपलब्ध कराए।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

च. <u>विविध</u> अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान जांच से पहले, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की आड़ में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दो जांचें शुरू की हैं।

ख. दोनों मामलों में, प्राधिकारी ने *प्रथम दृष्टया* पाया है कि इन जांचों को शुरू करने के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद था।

ग. तथापि, दोनों मामलों में शुल्कों की सिफारिश करने का कोई आधार नहीं था। स्पष्ट रूप से, दोनों मामलों में जांच समाप्त होने तक पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी का *प्रथम दृष्टया* आकलन पलट दिया गया था।

घ. वर्तमान जांच में ईरान को शामिल न करने के बाद, आवेदक पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार ईरान से आयात के प्रभाव को कम करने के बाद आंकड़ों को फिर से प्रस्तुत करने का दायित्व था।

ङ. वर्तमान जांच क्षेत्राधिकार के बाहर है क्योंकि आवेदन-पत्र दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमोदन के बिना घरेलू उद्योग द्वारा वापस ले लिया गया था।

च.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

24. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. पहली जाँच जनवरी-सितंबर 2019 की जाँच अवधि के लिए 2019 में शुरू की गई थी। कार्यवाही के दौरान, आवेदकों ने जांच की शुरुआत के चरण की बजाय संबद्ध देशों से अधिक पाटन पाया। इसके अतिरिक्त, पहले आवेदन-पत्र में जाँच अवधि के आँकड़े जाँच अवधि के बाद की बाज़ार वास्तविकताओं को नहीं दर्शाते थे, क्योंकि पाटन के स्रोत बदल गए थे।

ख. दूसरे आवेदन-पत्र में, प्राधिकारी ने पाया कि कुवैत और सऊदी अरब के निर्यातक संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे थे, लेकिन यह माना कि कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने संबंधित जाँच अवधि (जनवरी-दिसंबर 2020) के दौरान बिक्री लागत पर 20% लाभ अर्जित किया। घरेलू उद्योग ने इसे सेस्टैट के समक्ष चुनौती दी, जिसने पुनः जाँच का निर्देश दिया। हालाँकि, उस जाँच अवधि के बाद से लगभग तीन वर्ष बीत जाने और पाटन व क्षति की स्थिति बिगड़ जाने के कारण, एक नया आवेदन-पत्र दायर किया गया और दूसरा आवेदन-पत्र वापस ले लिया गया।

ग. प्राधिकारी के समक्ष बार-बार किए गए आवेदनों से भारतीय एमईजी उद्योग की कमजोर स्थिति का पता चलता है, तथा कुवैत और सऊदी अरब के निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों का खुलासा होता है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

25. प्राधिकारी ने जाँच की शुरूआत के चरण में साक्ष्य की पर्याप्तता की जाँच की। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिये थे, जिसके आधार पर प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच शुरू की थी।

26. प्राधिकारी ने पिछली जाँच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के साथ-साथ अपने स्वयं के जांच परिणामों पर भी विचार किया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट

करते हैं कि प्रत्येक जाँच, उस विशिष्ट जाँच से संबंधित अवधि के तथ्यों के आधार पर की जानी है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मर्जिन</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. सामान्य मूल्य की गणना करने की घरेलू उद्योग की पद्धति गलत है क्योंकि इसमें संबद्ध देशों में उत्पादकों की घरेलू बिक्री पर विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(i) के अंतर्गत, निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तर में घोषित उत्पादक/निर्यातक की घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं। तथापि, यदि इस आधार के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश को की गई बिक्री के आधार पर किया जा सकता है।

ख. एसएबीआईसी समूह ने अपने घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्री [***%] की है। सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार की जानी है, जब तक कि कंपनी के रिकॉर्ड जीएएपी के अनुरूप न हों या रिकॉर्ड उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से न दर्शाते हों। एसएबीआईसी समूह ने तीसरे देश के बिक्री आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं।

ग. एसजीएंडए लागत और लाभ उत्पादक के उत्पादन और बिक्री से संबंधित वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए, जब तक कि व्यापार के सामान्य क्रम में कोई बिक्री न हो।

घ. एशियाई संविदा कीमत ("एसीपी") वह आधार नहीं है जिस पर भारत सहित एशिया में एमईजी की वार्षिक या स्थल बिक्री की जाती है। बल्कि इसका उपयोग दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर 7-15 वर्षों तक होते हैं। इक्वेट ग्रुप ने कई देशों में विचाराधीन उत्पाद की वार्षिक खरीद संविदा प्रस्तुत की है, एक तथ्य जिसे घरेलू उद्योग ने पिछली जांच में स्वीकार किया था जो औसत चीन सीएफआर कीमतों पर चिह्नित हैं।

भारत को निर्यात कीमत की एसीपी के साथ तुलना अनुचित है और आवेदक द्वारा एक कृत्रिम और बढ़ी-चढ़ी कीमत अंतर बनाने का प्रयास है।

ङ. भारत को इक्वेट ग्रुप की औसत निर्यात कीमत जांच की अवधि के दौरान चीन या पाकिस्तान से अधिक थी।

च. पीआरसी ने जांच की अवधि के दौरान न तो भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और न ही घरेलू बिक्री की है। हालाँकि, इसने जाँच में भाग लिया है क्योंकि यह सऊदी अरामको की साझा शेयरधारिता के कारण एसएबीआईसी समूह का एक संबद्ध पक्षकार है। एलडीपीई जाँच में प्राधिकारी ने पीआरसी और सदारा को संबद्ध माना था और उन्हें शुल्क की एक ही दर प्रदान की थी।

छ. इक्वेट समूह ने वर्तमान जाँच में पूर्ण सहयोग किया है और घरेलू बिक्री की नगण्य मात्रा को देखते हुए, सामान्य मूल्य की गणना मूल देश में सीओपी के आधार पर तथा उचित मात्रा में एसजीएंडए और लाभ के आधार पर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप, प्राधिकारी को उचित राशि के रूप में 5% प्रतिशत का लाभ मार्जिन अपनाना चाहिए। इक्वेट समूह ने अपने विश्लेषण में प्राधिकारी की सहायता के लिए तीसरे देश के बिक्री आँकड़े भी दिए हैं।

ज. टीकेओसी के वित्तीय विवरणों पर भरोसा करना गलत है क्योंकि यह जांच की अवधि से संबंधित नहीं है और यह इक्वेट निष्पादन को ध्यान में नहीं रखता है। टीकेओसी के वित्तीय विवरणों में सूचित लाभ मार्जिन एथिलीन और एमईजी के लिए हैं और इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के लिए उचित लाभ मार्जिन निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

झ. कारपोरेट स्तर की लाभप्रदता सामान्य वाणिज्यिक एमईजी बिक्री से परे कई कारकों से प्रभावित होती है जैसे दीर्घकालिक आपूर्ति करार, एकीकरण लाभ और अन्य कार्य-नीतिक प्रचालन। इक्वेट ग्रुप ने एमईजी से संबंधित उत्पाद विशिष्ट लागत और बिक्री की सूचना दी है और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार, निर्मित सामान्य मूल्य निर्यातकों के रिकॉर्ड के आधार पर

निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत दीर्घ अवधि की शर्तें पूरी की जा रही हैं।

ञ. पीएमएस को सीटीए या पाटनरोधी नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है। विशेषण "विशिष्ट" और "बाजार" के प्रयोग से संकेत मिलता है कि बाजार की स्थिति 'अपवादात्मक, विशिष्ट, व्यक्तिगत, एकल, विशिष्ट' होनी चाहिए और पीएमएस सिद्ध करने के लिए प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बाजार में कार्यों की अपवादात्मक/विशिष्ट स्थिति मौजूद है।

ट. भारतीय कानून और विश्व व्यापार संगठन करार इनपुट/कच्चे माल के बाजार में पीएमएस की जांच की अनुमति नहीं देते हैं। घरेलू उद्योग ने यह दावा करने के लिए यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका के कानूनों का हवाला देकर प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये देश इनपुट के लिए पीएमएस पर विचार करते हैं। ऐसे देशों में नगरपालिका कानून भारत से काफी अलग है।

ठ. यूरोपीय संघ के पाटनरोधी शुल्क विनियमन में कच्चे माल की विकृति के प्रावधान भारतीय कानून में मौजूद नहीं हैं और इसलिए, इस संबंध में यूरोपीय संघ का व्यवहार असंगत है।

ड. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 में सभी संदर्भ समान उत्पाद या विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं, इसलिए, यह प्राधिकारी को इनपुट में विकृति के आरोप की जांच करने की अनुमति नहीं देता है।

ढ. पीएमएस सिद्ध करने के लिए सबूत का भार आवेदक पर है और उसने कुवैत या सऊदी अरब के लिए इसे सिद्ध नहीं किया है जैसा कि पैनल ने यूएस-शर्ट्स एंड ब्लाउज़ में माना है। आवेदक ने पिछली जांचों में भी पीएमएस के गलत कानूनी मानक पर विश्वास किया है।

ण. आवेदक के अनुरोध अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हैं कि फीडस्टॉक गैसों के कीमत निर्धारण पर कथित सरकारी नियंत्रण पीएमएस के दावे को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक का पीएमएस

आरोप पीयूसी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त फीडस्टॉक से संबंधित है, न कि स्वयं विचाराधीन उत्पाद से।

त. सऊदी अरब सरकार ("जीकेएसए") द्वारा प्राकृतिक गैस या तरल पदार्थों की कीमतों के विनियमन को "इनपुट और फीडस्टॉक की आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट स्थिति" नहीं माना जा सकता। भारत सरकार सहित सभी सरकारों द्वारा ऐसे नियामक उपाय अपनाए जाते हैं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि ऐसे उपाय देश के भीतर इनपुट के बाजार को कैसे विकृत करते हैं।

थ. आवेदकों ने कीमतों के मात्र विनियमन को विकृति के समान बताया है। इसके अतिरिक्त, मात्र सरकारी उपाय की मौजूदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एमईजी के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतें उचित रूप से नही दर्शाई गई हैं या यह सिद्ध नहीं होता है कि घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना नहीं की जा सकती है।

द. निर्यातकों की बहियों में दर्ज लागत को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनपुट कीमतें राज्य द्वारा विनियमित की जा रही हैं या क्योंकि विनियमन की मौजूदगी के कारण इनपुट कीमतें कथित रूप से अनुचित हैं। अर्जेंटीना निर्यात कर प्रणाली के कारण इनपुट की घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम होने के बावजूद, ईयू-बायोडीजल (अर्जेंटीना) में अपीलीय निकाय ने माना कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था कि उत्पादक के रिकॉर्ड बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री की लागत को उचित रूप से नहीं दर्शाते हैं। यूक्रेन -अमोनियम नाइट्रेट (रूस) और यूरोपीय संघ-लागत समायोजन पद्धतियां (रूस) में अपीलीय निकाय द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसके अतिरिक्त, "उपयुक्त रूप से दर्शाना" यह दर्शाता है कि निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की केवल सत्यता और सटीकता की ही जांच की जा सकती है और क्या ऐसे रिकॉर्ड जांचे गए उत्पादक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में वास्तव में किए गए खर्चों के उपयुक्त और पर्याप्त रूप से अनुरूप हैं।

ध. आवेदक ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि केएसए में कीमत समतुल्यता का सिद्धांत मौजूद है या यह कि केएसए में निर्यातक संबद्ध सामानों के विनिर्माण में ऐसी व्यवस्था से लाभान्वित होते हैं।

न. ईयू-बायोडीजल के अनुसार, जांच प्राधिकारी "देश में उत्पादन लागत" को आवेदक द्वारा सुझाए गए एथिलीन बेंचमार्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

प. *अनकोटेड कॉपियर पेपर* में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कानूनी मानक के अनुसार, घरेलू उद्योग को यह साबित करना होगा कि सरकारी हस्तक्षेप से घरेलू बाजार में कीमतें कम हुई हैं।

फ. ऑस्ट्रेलिया - A4 कॉपी पेपर पर निर्भरता इस कारण से त्रुटिपूर्ण है कि पैनल ने इंडोनेशिया के इस दावे पर कहीं भी अपने जांच परिणाम नहीं दिए हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित "विशेष बाजार स्थिति" शब्द का उपयोग इनपुट की लागत में विकृतियों को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

ब. जीकेएसए में ईथेन का कीमत निर्धारण वाणिज्यिक कारणों और पर्यावरणीय चिंताओं के संयोजन पर आधारित है, इसके अलावा प्रोपेन और ब्यूटेन के लिए, जीकेएसए ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत सूत्र निर्धारित किया है कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर आधारित हों। फीडस्टॉक की कीमतों को बाजार कीमतों से जोड़ने से यह सुनिश्चित होता है कि कीमतें वाणिज्यिक विचारों पर आधारित हों और उत्पादकों को पूरी लागत वसूलने और व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में लाभ कमाने में सक्षम बनाती हों। इसे केएसए के डब्ल्यूटीओ अभिगम वार्ता के दौरान कार्यकारी पक्षकार द्वारा स्वीकार किया गया था।

भ. ईथेन के लिए निर्धारित कीमतों का उपयोग निर्यात बाजारों के लिए या केएसए के अंतर्गत खपत के लिए निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तदनुसार, कीमत तुलनीयता प्रभावित नहीं होती है।

म. यूरोपीय आयोग ने अपनी एमईजी जांच में अपनी बहियों में दर्ज एसएबीआईसी समूह की उत्पादन लागत पर भरोसा किया था।

य. यूएसडीओसी ने कई जांचों में सरकारी नियंत्रण को पीएमएस के गठन के लिए अपर्याप्त साक्ष्य माना है।

कक. आवेदक का पीएमएस पर आरोप जीकेएसए द्वारा कथित सब्सिडी से जुड़ा है, तथापि, ऐसे कथित कार्यक्रमों का कोई विवरण नहीं दिया गया। यदि ऐसी कथित योजनाओं के साक्ष्य को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो उचित उपाय प्रतिकारी शुल्क होगा, न कि पाटनरोधी शुल्क।

खख. आवेदक का तीसरे देश की निर्यात कीमतों से संबंधित वेबसाइटों पर भरोसा करना अनुचित है। एसएबीआईसी समूह ने तीसरे देश की कीमत दी हैं, जो वास्तव में दर्शाता है कि ये कीमत भारत के बराबर हैं।

गग. केएसए में पीएमएस की मौजूदगी से लागतों को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पीएमएस निर्यात और घरेलू कीमतों के बीच उचित तुलना को रोकता है। आवेदक लागत की 'उचितता' और "क्या लागतें संबद्ध सामानों के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से दर्शाती हैं" के बीच अंतर करने में विफल रहा है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2, ऑस्ट्रेलिया में पैनल की रिपोर्ट - ए4 कॉपी पेपर और ईईसी - कॉटन यार्न के संदर्भ में, प्राधिकारी को यह पता लगाना होगा कि क्या पीएमएस की मौजूदगी घरेलू बिक्री की निर्यात बिक्री के साथ उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है।

घघ. घरेलू और निर्यात दोनों उत्पादों के लिए उत्पादन लागत समान है, दोनों प्रकार की बिक्री के लिए कोई अलग-अलग लागत दर्ज नहीं की जाती है और विचाराधीन उत्पाद दोनों बाजारों में बाजार निर्धारित दरों पर बेचे जाते हैं।

डड. केएसए और कुवैत के मामले में, यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना

अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, पिछली जांच में भले ही प्राधिकारी ने केएसए में पीएमएस की मौजूदगी का निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने केएसए से निर्यातकों की वास्तविक लागतों को खारिज नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, भले ही आवेदक के पीएमएस से संबंधित आरोप सही पाए जाते हैं, प्रतिवादियों की दर्ज लागतों को खारिज करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

चच. पिछली जांच में पीएमएस के जांच परिणाम के बावजूद, प्राधिकारी ने केएसए के उत्पादकों की दर्ज उत्पादन लागत में कोई समायोजन नहीं किया।

छछ. किसी विशेष वस्तु की कम कीमत को पीएमएस नहीं माना जा सकता है। यदि क्षेत्रीय लाभों के कारण ऐसी लागतें कम हैं तो लागतों को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक लाभ को पीएमएस नहीं माना जा सकता है।

जज. एसओके के विरुद्ध पीएमएस के आरोप को पुष्ट करने या पीएमएस पर एसओके के विरुद्ध प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों का खंडन करने के लिए कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदक ने केएसए और एसओके में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का उल्लेख किया है, परन्तु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि एसओके सरकार ("जीएसओके") इनपुट सामग्रियों की बिक्री पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है जिससे घरेलू कीमतें विकृत होती हैं या सामान्य मूल्य की गणना के लिए घरेलू कीमतें अविश्वसनीय हो जाती हैं। केवल यह तथ्य कि कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, पीएमएस के आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

झझ. आवेदक ने वह कथित शाही आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर उसने पीएमएस का दावा किया है।

ञञ. कोई एकीकृत जीसीसी बाजार नहीं है और विभिन्न फीडस्टॉक उत्पादक फीडस्टॉक की कीमतें अलग-अलग रखते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने एसओके और केएसए के निर्यातकों की उत्पादन लागत की तुलना अंतर्राष्ट्रीय एथिलीन निर्धारण कीमतों से करने का अनुरोध किया है,

जिसका आवेदक ने अगोपनीय रूपांतर में खुलासा नहीं किया है, और दावा किया है कि कच्चे माल की कम लागत पीएमएस में योगदान करती है। केवल एसओके में इनपुट की कम कीमतें पीएमएस के होने का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। खाड़ी क्षेत्र, सऊदी अरब और अमेरिका में कम कीमतें प्राकृतिक प्रतिस्पर्धात्मक और क्षेत्रीय लाभों के कारण हैं, जिनमें तेल और गैस संसाधनों तक प्रचुर पहुंच शामिल है, न कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण, जैसा कि आवेदक ने आरोप लगाया है।

टट. घरेलू उद्योग आयातित फीडस्टॉक पर निर्भर करता है जिससे भारत में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।

ठठ. अपर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल की उपलब्धता के मुद्दे की जांच केवल सब्सिडी-रोधी जांच के माध्यम से की जा सकती है, जैसा कि प्राधिकारी ने *अनकोटेड कॉपियर पेपर* (फा.सं. 6/32/2017-डीजीएडी) में माना है। कथित "वित्तीय योगदान" की जांच केवल प्रतिकारी शुल्क जांच में ही की जा सकती है।

डड. प्राधिकारी ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से क्लियर फ्लोट ग्लास में केएसए में पीएमएस के दावों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, कतर, केएसए, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से एलडीपीई में, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला था कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं थे कि क्या पीएमएस ने घरेलू बिक्री और निर्यात कीमत के बीच उचित और निष्पक्ष तुलना को रोका था।

ढढ. जब मामले की पहले ही विस्तृत जांच हो चुकी हो तो विस्तृत पीएमएस प्रश्नावली जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. किसी भी प्रतिभागी निर्यातक ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि वे भारत में संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे हैं।

ख. एशियाई क्षेत्र और भारत के लिए निर्यातकों द्वारा प्रकाशित मासिक संविदा कीमतें निर्यातकों द्वारा पाटन के स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस संबंध में, आवेदक ने जांच की अवधि के लिए इक्वेट समूह की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एशियाई संविदा कीमत पर विश्वास किया है, जो दर्शाता है कि भारतीय संविदा कीमतों और एशियाई संविदा कीमतों के बीच औसत कीमत अंतर कम से कम 300 अमेरिकी डॉलर है।

ग. एसएबीआईसी समूह अन्य एशियाई बाजारों में भारत की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर बिक्री करता है, जिसमें एशियाई संविदा कीमतों और भारत को वास्तविक निर्यात कीमत के बीच का अंतर लगभग 300 अमेरिकी डॉलर है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक ने गौण स्रोत (अर्गाम वेबसाइट) पर प्रकाशित नवंबर, 2023 माह के एशियाई संविदा कीमत पर भरोसा किया है।

घ. निर्यातकों का यह दावा कि एशियाई संविदा कीमतें 7-15 वर्षों के दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए तय की जाती हैं, भ्रामक है, क्योंकि इस बात का कोई तर्क नहीं है कि ऐसे दीर्घकालिक करारों के लिए मासिक कीमतें क्यों घोषित की जाएंगी। यह दूसरी मौखिक सुनवाई के दौरान एसएबीआईसी समूह के अपने ही बयान का खंडन करता है, जहाँ उसने दावा किया था कि एशियाई संविदा कीमतें 1-2-वर्षीय संविदाओं के लिए हैं। इसके अलावा, एमईग्लोबल (इक्वेट समूह का एक हिस्सा) की वेबसाइट स्पष्ट रूप से बताती है कि एशियाई संविदा कीमतें एशियाई बाजार में अल्पकालिक मांग-आपूर्ति गतिशीलता को दर्शाते हैं।

ड. यह भी स्पष्ट नहीं है कि जब भारतीय संविदा कीमत कुवैत से भारत में एमईजी की वास्तविक आयात कीमत के लगभग बराबर हैं, तो एशियाई संविदा कीमतें एशियाई देशों को निर्यात कीमतों को क्यों नहीं दर्शाएँगे, जब तक कि कुवैत के निर्यातक अन्य एशियाई बाजारों में अपने निर्यात में व्यापार विकृत कार्यकलापों में भी शामिल न हों।

च. कुवैत के निर्यातकों ने निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की मांग की है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(सी) के अनुसार, जहां घरेलू या तीसरे देश की बिक्री उपलब्ध नहीं है, वहां बिक्री की लागत और उचित लाभ का उपयोग करके सामान्य मूल्य का निर्माण किया जाना है। प्राधिकारी को सीएनवी की गणना के लिए उनके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ पर विचार करना चाहिए।

छ. आवेदक ने दोनों संबद्ध देशों के मामले में विशेष बाजार स्थिति के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं।

ज. सऊदी अरब और कुवैत के बाजार, और सामान्य रूप से, खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र, प्रमुख इनपुट और यूटिलिटियों की कीमत निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप के कारण एक विशेष बाजार स्थिति से प्रभावित हैं। यह हस्तक्षेप प्रमुख कच्चे माल और यूटिलिटियों की लागत को विकृत करता है, और परिणामस्वरूप, उत्पादकों के रिकॉर्ड में दर्शाई गई लागतें संबद्ध सामानों के उत्पादन से जुड़ी लागतों को उचित रूप से नहीं दर्शाती हैं। अत:, पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ऐसी लागतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया करने के लिए। इस संबंध में, आवेदक पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 पर भरोसा करता है, जो दर्ज की गई लागतों से विचलन की अनुमति देता है जहां वे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से नहीं दर्शाती।

झ. यदि अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा बताई गई उत्पादन लागत को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, बशर्ते कि उसे ऐसी लागतों की उपेक्षा करने का कोई ठोस कारण मिले।

ञ. आवेदक का कहना है कि एक बार किसी विशेष बाजार स्थिति के आरोप का समर्थन करने के लिए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रदान कर दिए जाने के बाद, एसओके के मामले में, यह साबित करने का भार संबंधित देश के निर्यातकों पर है कि विशेष बाजार स्थिति मौजूद नहीं है।

ट. सऊदी अरब सरकार, गैस आपूर्ति एवं कीमत निर्धारण विनियमन कानून और इसके कार्यान्वयन विनियमन के माध्यम से, कुछ हाइड्रोकार्बन की कीमत निर्धारण को नियंत्रित करती है जिनका उपयोग संबद्ध सामानों के उत्पादन में इनपुट या यूटिलिटियों के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक एक कीमत समतुल्यन व्यवस्था लागू है जिसके तहत सरकार सऊदी अरामको को इन विनियमित गैस उत्पादों को निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को बेचने में हुए नुकसान की भरपाई करती है। इस व्यवस्था को सऊदी अरब सरकार ने अपनी व्यापार नीति समीक्षा में स्वीकार किया है।

ठ. दोहरी कीमत निर्धारण व्यवस्था के तहत, सऊदी अरब सरकार के अधीन ऊर्जा मंत्रालय, अरामको को विनियमित घरेलू कीमतों पर निचले स्तर के उत्पादकों को विनियमित गैस उत्पादों की आपूर्ति करने का आदेश देती है। सऊदी अरब सरकार इन विनियमित दरों पर इनपुट बेचने से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अरामको को करती है।

ड. एसएबीआईसी समूह का यह तर्क कि इनपुट और फीडस्टॉक मूल्य विनियमन से संबंधित "साधारण सरकारी उपाय" पीएमएस का गठन नहीं कर सकते, पूरी तरह से गलत है। इस संबंध में- ए 4 कॉपी पेपर में पैनल के निर्णय पर भरोसा किया गया है। तदनुसार, साधारण सरकारी उपाय भी एक विशेष बाजार स्थिति को बढ़ा सकते हैं यदि वे बाजार विकृतियों का कारण बनते हैं।

ढ. पिछली जांच में भी, प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला था कि विनियमित गैस उत्पादों के कीमत विनियमन से सऊदी अरब में विशेष बाजार स्थिति उत्पन्न होती है।

ण. कुवैत में भी इसी तरह की विकृतियाँ मौजूद होने की संभावना है, हालाँकि सीमित पारदर्शिता के कारण, विकृति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं किया जा सका। बाजार की खुफिया सूचना के आधार पर, कुवैत सरकार ने एक शाही डिक्री जारी की है, जिसमें इक्वेट समूह के दो निर्यातकों को सरकारी

आपूर्तिकर्ता से काफी कम दरों पर प्रमुख फीडस्टॉक खरीदने की अनुमति दी गई है।

त. एमईजी की बिक्री पर इक्वेट समूह द्वारा अर्जित लाभ सऊदी अरब के निर्यातकों से भी अधिक है। एमईजी उत्पादन की कुल लागत में एथिलीन की पर्याप्त हिस्सेदारी को देखते हुए, आवेदक का मानना है कि कुवैत के निर्यातकों को कच्चे माल और यूटिलिटी लागतों से लाभ होता है जो सऊदी अरब के निर्यातकों की पहले से ही विकृत लागतों से भी कम हैं।

थ. इक्वेट ग्रुप के इस दावे के उत्तर में कि कम इनपुट लागतें तब तक एक विशेष बाजार स्थिति नहीं बना सकतीं जब तक कि वे सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना को बाधित न करें, आवेदक का अनुरोध है कि एक विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी और कीमत तुलनीयता पर इसका प्रभाव दो अलग-अलग कानूनी परीक्षण हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर में पैनल द्वारा स्पष्ट किया गया है।

द. यदि निचले स्तर की कंपनियों को प्राकृतिक गैस या इनपुट आपूर्तिकर्ता वास्तव में विनियमित घरेलू कीमतों पर बिक्री करते हुए पूर्ण लागत वसूली के आधार पर काम कर रहे थे, तो सऊदी अरब सरकार को उन्हें मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

ध. यह तथ्य कि एक विशेष बाजार स्थिति की ओर ले जाने वाला एक सरकारी उपाय सब्सिडी के रूप में भी पात्र हो सकता है, प्राधिकारी को निर्यातक देश में संबद्ध सामानों की लागत और कीमतों पर इसके प्रभाव की जांच करने से नहीं रोकता है। इस संबंध में *ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर* मामले में पैनल के फैसले पर विश्वास किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी विशेष बाजार स्थिति का निष्कर्ष किसी सब्सिडी के खिलाफ कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं है।

न. ऑस्ट्रेलिया ए4-कॉपी पेपर पैनल ने बहुत स्पष्ट रूप से पाया कि "बाज़ार की स्थिति विशिष्ट, व्यक्तिगत, एकल, विशिष्ट होनी चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह असामान्य या असाधारण हो - अर्थात अपवादात्मक"

तर्क यह है कि ऐसी स्थिति में सामान्य सरकारी उपायों को भी रोका नहीं जा सकता जहाँ ऐसे उपाय किसी विशेष बाज़ार स्थिति को जन्म देते हों।

प. प्राधिकारी ने पिछली जाँच में सऊदी अरब में विशेष बाज़ार स्थिति की मौजूदगी की स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी।

फ. जब पीएमएस सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों को प्रभावित करता है, तब भी यह कीमत तुलनीयता पर इसके प्रभाव को नकारता नहीं है। *ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर* में पैनल ने जाँच अधिकारियों को केवल इसलिए गैर-तुलनीयता पर निष्कर्ष देने से नहीं रोका क्योंकि घरेलू और निर्यात दोनों उत्पादन में समान इनपुट का उपयोग किया जाता है। पैनल ने स्पष्ट रूप से पाया कि जब घरेलू और निर्यात दोनों बाज़ारों के लिए सामानों के उत्पादन में विकृत इनपुट का उपयोग किया जाता है, तब भी निर्यातक मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर, बाज़ारों में ऐसी विकृत लागतों का अलग-अलग लाभ उठा सकते हैं।

ब. यूरोपीय आयोग ने पहले ही 2021 में एसएबीआईसी समूह और एमईजीलोबल अमेरिकास इंक., जो कि इक्वेट समूह का एक संबंधित पक्षकार है, द्वारा निर्यातित एमईजी पर क्रमशः 7.7% और 46.7% पाटनरोधी शुल्क लगाया है, जो यह भी दर्शाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातक अनुचित व्यापार परिपाटियों को अपनाते हैं और तीसरे देश के बाजारों में भी पाटित कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं।

भ. पिछली जांच में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने से पहले लागत, कीमत निर्धारण और लाभप्रदता का आकलन करने में विफल रहे कि विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी ने कीमत तुलनीयता को प्रभावित नहीं किया।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

30. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केएसए और एसओके में निर्यात विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी का दावा किया है। केएसए के संबंध में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि केएसए सरकार कीमत समतुल्यन व्यवस्था के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त विनियमित गैस उत्पादों के लिए दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति संचालित करती है, जिसके अंतर्गत वह निचले स्तर के उद्योग को ऐसे इनपुट (ईथेन, प्रोपेन आदि) की आपूर्ति के लिए कीमत निर्धारित करती है। घरेलू उद्योग ने यह दावा करने के लिए सऊदी अरब की व्यापार नीति समीक्षा और सऊदी अरामको की वार्षिक रिपोर्ट के उद्धरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त,

एसओके के संबंध में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि एसओके के एकीकृत जीसीसी बाजार का हिस्सा होने के कारण, जिसमें विकृत कीमतें मौजूद हैं, एसओके में फीडस्टॉक की कीमतें भी विकृत हैं।

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पीएमएस की मौजूदगी के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे पर विवाद किया है। एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि केएसए में कोई कीमत समतुल्यन व्यवस्था नहीं है और घरेलू उद्योग द्वारा कथित विकृत कीमत निर्धारण उपाय केएसए सरकार द्वारा सामान्य कीमत विनियमन हैं, जैसा कि विश्व- भर में सरकारों द्वारा किया जाता है।

33. केएसए के संबंध में, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, विशेष रूप से सऊदी अरामको की वार्षिक रिपोर्ट, और कुवैत, सऊदी अरब और अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों के आधार पर, प्राधिकारी को केएएए में पीएमएस की मौजूदगी के संबंध में अपने पिछले निष्कर्ष से विचलित होने का कोई कारण नहीं मिलता है। तथापि, प्राधिकारी को रिकॉर्ड में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं मिले हैं कि ऐसी विकृति निर्यात कीमत और घरेलू कीमत के बीच तुलनीयता को प्रभावित करती हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने केएसए के उत्पादकों की उत्पादन लागत में पीएमएस के आरोप के आधार पर कोई समायोजन नहीं किया है।

34. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को जांच अवधि के दौरान एसओके में पीएमएस के की मौजूदगी के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। तदनुसार, एसओके के उत्पादकों के मामले में पीएमएस के कारण कोई समायोजन नहीं किया गया है।

35. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दिए अनुसार निर्धारित की गई है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क) एसओके के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

इक्वेट समूह के लिए सामान्य मूल्य

(ख) इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी ("इक्वेट")

36. उत्पादक ने जांच की अवधि में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है, जो उसके असंबद्ध पक्षकारों को किया गया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के निमित्त के समायोजनों का दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री, इक्वेट द्वारा भारत को की गई कुल निर्यात बिक्री मात्रा के 5% से कम है और तदनुसार, इक्वेट द्वारा की गई घरेलू बिक्री पर्याप्तता परीक्षण के लिए योग्य नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु ऐसी बिक्री पर विचार नहीं किया है।

37. अपने प्रश्नावली के उत्तर में, इक्वेट ने उत्पादन लागत, उचित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने मूल देश में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें बिक्री और प्रशासनिक व्ययों को उचित रूप से जोड़ा गया है और लाभ मार्जिन भी जोड़ा गया है। इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

(ग) दि कुवैत ओलेफिन्स कंपनी ("टीकेओसी")

38. उत्पादक ने जांच की अवधि में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। तथापि, टीकेओसी की सभी घरेलू बिक्री उसके संबद्ध पक्षकार, इक्वेट को की गई है, जिसने संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और इसीलिए, एसओके के घरेलू बाजार में उनकी खपत नहीं हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए टीकेओसी की घरेलू बिक्री पर विचार नहीं किया है।

39. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि टीकेओसी ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में निर्मित सामान्य मूल्य अर्थात उत्पादन लागत तथा उचित बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना का दावा किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने मूल देश में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है, जिसमें बिक्री और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत, सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

40. एसओके से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

ख) एसओके के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

इक्वेट समूह के लिए निर्यात कीमत

(घ) इक्वेट

41. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। इक्वेट ने प्रत्यक्ष निर्यात के साथ-साथ असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से भी निर्यात किया है। मित्सुबिशी कारपोरेशन को छोड़कर, किसी अन्य असंबद्ध व्यापारी ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। इक्वेट ने शिपिंग पोत-परिवहन लागत, बैंक शुल्क और एलसी डिस्काउंटिंग प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है। इक्वेट समूह ने इक्वेट समूह के अलावा अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को भी बेचा है। ऐसे लेनदेन को इक्वेट समूह के लिए पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन की गणना के लिए नहीं माना गया है, और ऐसे अन्य उत्पादकों के लिए विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

(ड.) टीकेओसी

42. टीकेओसी ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। टीकेओसी ने भारत को कोई प्रत्यक्ष बिक्री नहीं की है, और इसकी सभी बिक्री या तो इसके संबद्ध व्यापारी इक्वेट या असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से की गई है। मित्सुबिशी कारपोरेशन को छोड़कर, किसी अन्य असंबद्ध व्यापारी ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। तथापि, टीकेओसी द्वारा भारत को निर्यात की गई कुल मात्रा के संदर्भ में ऐसे लेनदेन नगण्य हैं। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

43. एसओके के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

ख) केएसए के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

एसएबीआईसी समूह के लिए सामान्य मूल्य

44. एसएबीआईसी समूह के निम्नलिखित उत्पादकों ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है:

(i) अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेमिया),

(ii) ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (शार्क);

(iii) जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड),

(iv) सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी (सऊदी कायन),

(v) सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट);

(vi) यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब);

(vii) रबीग रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी (रबीग)।

45. प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच की अवधि के दौरान, केवल शार्क और यानपेट ने सऊदी अरब के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। घरेलू बाजार में सभी बिक्री संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी को की गई, जिसने संबद्ध सामानों को असंबद्ध घरेलू ग्राहकों को बेचा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पेट्रोकेमिया, यूनाइटेड, सऊदी कायन और यानसब द्वारा विचाराधीन उत्पाद की कोई घरेलू बिक्री नहीं की गई है।

(क) शार्क के लिए सामान्य मूल्य

46. शार्क ने अपने घरेलू बाजार में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। सभी घरेलू बिक्री उसके संबद्ध व्यापारी एसएबीआईसी के माध्यम से की गई थी। शार्क की घरेलू बिक्री भारत को उसके निर्यात बिक्री मात्रा के 5% से अधिक है और इसलिए, उनका मानना है कि शार्क मात्रा में पर्याप्त है। प्राधिकारी ने लाभदायक लेनदेन की जांच के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण भी किया। जांच करने पर, यह पाया गया कि ***% से अधिक बिक्री उत्पादन लागत से कम पर की गई थी। तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने केवल लाभप्रद बिक्री पर ही विचार किया है। शार्क ने संभारिकी

के लिए समायोजन का दावा किया है और डेस्क सत्यापन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

(ख) पेट्रोकेमिया, सऊदी कायन, यूनाइटेड के लिए सामान्य मूल्य

47. पेट्रोकेमिया, सऊदी कायन और यूनाइटेड ने जांच अवधि में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री नहीं की है। उपर्युक्त उत्पादकों ने तीसरे देश के निर्यात प्रस्तुत किए हैं। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि एसएबीआईसी समूह अन्य क्षेत्राधिकारों में पाटन करता पाया गया है, प्राधिकारी तीसरे देश के निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं समझते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने बिक्री और प्रशासनिक व्ययों और लाभों को उचित रूप से जोड़कर मूल देश में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित किया गया है।

(ग) यांसाब, यानपेट और रबीग के लिए सामान्य मूल्य

48. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यानसब, यानपेट और पीआरसी ने भी वर्तमान जाँच में भाग लिया है। तथापि, इनमें से किसी ने भी जाँच अवधि में भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने उनके लिए सामान्य मूल्य/निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की है। हालाँकि, चूँकि ये उत्पादक एक ही समूह का हिस्सा हैं, इसलिए एसएबीआईसी समूह के लिए निर्धारित शुल्क मार्जिन इन निर्यातकों पर लागू होगा।

(घ) असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

49. केएसए के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

सऊदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

एसएबीआईसी समूह के लिए निर्यात कीमत

(क) शार्क के लिए निर्यात कीमत

50. शार्क ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिनका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। शार्क ने अपने संबद्ध व्यापारियों, एसएबीआईसी और एसपीडीसी के माध्यम से बिक्री की है। एसएबीआईसी ने अपनी संबद्ध कंपनी एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। एसपीडीसी ने अपने संबद्ध व्यापारी मित्सुबिशी कारपोरेशन के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। शार्क और उसके संबद्ध व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

(ख) पेट्रोकेमिया के लिए निर्यात कीमत

51. पेट्रोकेमिया ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। पेट्रोकेमिया ने अपने संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के माध्यम से बिक्री की है। पेट्रोकेमिया और उसके व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

(ग) सऊदी कायान के लिए निर्यात कीमत

52. सऊदी कायन ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। सऊदी कायन ने अपने संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के माध्यम से बिक्री की है। सऊदी कायन और उसके व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

(घ) यूनाइटेड के लिए निर्यात कीमत

53. यूनाइटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसका मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। यूनाइटेड ने अपने संबद्ध व्यापारी, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल के माध्यम से बिक्री की है। यूनाइटेड और उसके व्यापारियों ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, आउटसोर्सिंग शुल्क, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित की गई है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

54. केएसए से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में प्रस्तावित है।

आरओएस से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

55. आरओएस से संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है।

56. तदनुसार, आरओएस से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

57. आरओएस असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.2 पाटन मार्जिन

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसओके और केएसए दोनों के मामले में, प्रतिभागी निर्यातक एक-दूसरे से संबद्ध हैं और एक समूह हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने समूह के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। वर्तमान जाँच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	**सामान्य मूल्य (यूएसडॉ. /एमटी)**	**निवल निर्यात कीमत (यूएसडॉ. /एमटी)**	**पाटन मार्जिन (यूएसडॉ. /एमटी)**	**पाटन मार्जिन (%)**	**पाटन मार्जिन रेंज (%)**
एसओके					
इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	40-50%
कुवैत ओलेफिन्स कंपनी ("टीकेओसी")	***	***	***	***	0-10%
इक्वेट समूह भारित औसत	***	***	***	***	20-30%
अन्य	***	***	***	***	40-50%
केएसए					
अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	40-50%
ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	0-10%
जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	30-40%
सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	30-40%
एसएबीआईसी	***	***	***	***	20-30%

समूह भारित औसत					
अन्य	***	***	***	***	40-50%
आरओएस					
अन्य	***	***	***	***	40-50%

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को उचित क्षति आकलन के लिए आईजीएल के आंकड़ों की जांच करनी चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 9ख के अनुसार क्षति का आकलन भारत में 'स्थापित उद्योग' के लिए किया जाना होता है, न कि केवल आवेदक के लिए।

ख. प्राधिकारी ने प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) जैसी पिछली जांचों में अन्य घरेलू उत्पादकों से सूचना मांगी है। आईओसीएल और आईजीएल द्वारा गैर-प्रतिभागिता न होने के कारण, प्राधिकारी को इन दोनों उत्पादकों की गैर-प्रतिभागिता से निष्कर्ष निकालने चाहिए।

ग. आवेदक के सभी क्षति मानदंड आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में सुधार दर्शाते हैं। डीजीटीआर के पिछले जांच परिणामों के अनुसार, घरेलू उद्योग को दिसंबर 2020 तक कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, अनंतिम जांच परिणामों की सिफारिश न करना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही रही है।

घ. उत्तरदाता निर्यातकों के अनुसार, पाटन मार्जिन नकारात्मक है और तदनुसार, भले ही मानदंड क्षति के मामले का समर्थन करते हों, किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की जा सकती।

ड. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क न लगाने का निर्णय और पिछले आवेदन-पत्र को वापस लेना इस बात का प्रमाण है कि घरेलू उद्योग का मामला तुच्छ था।

पिछले आवेदन-पत्र को वापस लेने के बाद आरआईएल यूएसए इंक से आयात में वृद्धि हुई, जो आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने और वर्तमान आवेदन-पत्र को उचित ठहराने के लिए क्षति का भ्रम पैदा करने का एक प्रयास है।

च. 2020-21 से लगातार क्षति के संबंध में आवेदक का दावा कानूनी रूप से असमर्थनीय है क्योंकि प्राधिकारी ने कोई वास्तविक क्षति न होने के आधार पर जांच समाप्त कर दी।

छ. भारत की उत्पादन क्षमता 27 लाख नहीं है, और आवेदकों को भारतीय उद्योग के वास्तविक उत्पादन और क्षमता के संबंध में सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को समग्र उपलब्ध क्षमता की गणना करते समय आरआईएल के सामने आई बंदी की स्थिति को अलग करना चाहिए।

ज. यह स्पष्ट नहीं है कि 27 लाख एमटी की घरेलू क्षमता की रिपोर्ट करते समय आरआईएल की कैप्टिव खपत पर विचार किया गया है या नहीं। यदि ऐसी कैप्टिव खपत को शामिल किया गया है, तो यह विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिक क्षमता का बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण है।

झ. ईरान को वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, भले ही ईरान से आयात कुल आयातों के 3% से अधिक थे (जैसा कि आवेदकों द्वारा दावा किया गया है) और तदनुसार, ईरान को वर्तमान जांच में शामिल किया जाना चाहिए था।

ञ. प्राधिकारी को एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की एक्सेल कॉपी विश्लेषण और टिप्पणियों के लिए साझा करनी चाहिए ताकि हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता कर सकें। आयात आंकड़े पक्षकार विशिष्ट नहीं है, तद्नुसार इसे गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता।

ट. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (ii) में "महत्वपूर्ण" शब्द यह दर्शाता है कि प्राधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ठ. वर्तमान जांच में कोई प्रतिकूल मात्रात्क प्रभाव नहीं है। 2022-23 और आधार वर्ष की तुलना में निरपेक्ष रूप से आयात की मात्रा में गिरावट आई है। आवेदक के इस दावे के विरोध में कि उक्त गिरावट क्यूसीओ लागू होने के कारण है, आयात की मात्रा में गिरावट घरेलू क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के कारण है।

ड. आयात के मात्रात्क प्रभाव के संबंध में आवेदक के दावे असंगत हैं और कथित क्षति के साथ कोई कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने में विफल हैं। आवेदक ने स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 तक, भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात आवश्यक था। फरवरी 2022 में आईओसीएल नई क्षमता चालू होने के साथ, घरेलू क्षमता की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो गई।

ढ. यह घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि पहले के आयात आपूर्ति की बाधाओं से प्रेरित थे, न कि आयातों की क्षतिकारक कीमत प्रभाव के कारण। उल्लेखनीय रूप से, जांच की अवधि के दौरान आयात में गिरावट आई, जो आईओसीएल के विस्तार के साथ मेल खाती है, जो भारतीय खरीदारों द्वारा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं की ओर स्वाभाविक परिवर्तन दर्शाती है। यदि कुवैत से आयात घरेलू उत्पादन का विस्थापन कर रहा होता, तो इस क्षमता विस्तार का आयात प्रवृत्तियों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

ण. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा में गिरावट स्पष्ट रूप से घरेलू सोर्सिंग की ओर परिवर्तन का संकेत देती है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में गिरावट यह दर्शाती है कि आयातों ने घरेलू उद्योग पर निरंतर मात्रा संबंधी दबाव नहीं डाला है।

त. कुल मांग में वृद्धि के बावजूद आयात में गिरावट आई है, जो दर्शाता है कि क्षति को संबद्ध देशों द्वारा एमईजी के आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

थ. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि उसने अपने निचले स्तर के मूल्यवर्धित उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध

सामानों का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है। यदि मौजूदा क्षमताएं भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है कि वह अन्य घरेलू उत्पादकों से इसे क्यों नहीं खरीद सका।

द. यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कीमत कटौती काफी है या आयात की कीमतों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर ह्रासमान या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।

ध. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष से ऊपर की ओर बढ़ी है, जो दर्शाती है कि घरेलू बिक्री कीमतों में कमी नहीं आई। जबकि बिक्री लागत में उतार-चढ़ाव आया है, बिक्री कीमत में गति बनी रही है और इसलिए, संबद्ध आयातों से जुड़ी कीमतों में कोई स्पष्ट न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है।

न. संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान कीमत कटौती समान रही है और घरेलू उद्योग का पहुँच कीमत और बिक्री कीमत एक साथ बढ़ी हैं।

प. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयात पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सीएफआर चीनी कीमत पर आधारित है। इस प्रकार, भारत में आयात कीमतों की कोई भूमिका नहीं है और इसीलिए, संबद्ध देशों से आयातित एमईजी का घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं हो सकता है।

फ. प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि आवेदकों द्वारा प्रदान की गई बिक्री कीमत के संबंध में सूचना गैर-कैप्टिव बिक्री के संबंध में है या कैप्टिव और गैर-कैप्टिव दोनों बिक्री के लिए है, ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई कीमत कटौती सही प्रतिनिधिकारक नहीं होगी।

ब. कोई कीमत कटौती नहीं हुई है, या यह केवल मामूली है।

भ. आवेदक द्वारा प्रदान की गई कीमत कटौती की गणना गलत है। आवेदक की व्युत्पन्न बिक्री कीमत जांच की अवधि के दौरान 40,886 रुपये प्रति एमटी है, जिसके आधार पर कीमत कटौती नकारात्मक है। इस प्रकार,

आवेदक का सकारात्मक और काफी कटौती से संबंधित दावा झूठा और भ्रामक है।

म. इसके अलावा, चीन - एक्स-रे उपकरण के मामले में, जहां कीमत कटौती नकारात्मक आती है, घरेलू उद्योग या प्राधिकारी के लिए यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ा सका और आयातों और कथित क्षति के बीच क्या कारणात्मकता है।

य. संबद्ध सामानों की कीमतें जांच की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर गिरीं, जिसमें गैर-संबद्ध देशों से निर्यात भी शामिल है और यह पाटन के कारण नहीं बल्कि चीन में कीमतों में गिरावट के कारण है, जो भारतीय बाजार के लिए निर्यातकों द्वारा अपनाया जाने वाला मानक है।

कक. घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि क्षमता उपयोग का वर्तमान स्तर, उच्च होने के बावजूद, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के कारण अपर्याप्त है।

खख. घरेलू उद्योग की बिक्री आधार वर्ष की तुलना में बढ़ी है। कैप्टिव खपत में 15 सूचकांक की कमी के बावजूद, कुल बिक्री मात्रा में केवल 14 सूचकांक की गिरावट आई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बिक्री में गिरावट कैप्टिव खपत में कमी और निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई थी।

गग. घरेलू उद्योग ने आयात किया है, जबकि उसके पास मालसूची थी और उसकी क्षमता उपयोग कम रही, जिससे यह आवश्यक निष्कर्ष निकलता है कि उसने वास्तविक कार्यशील क्षमता से अधिक क्षमता का अनुमान लगाया है।

घघ. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने मालसूची बढ़ने से बचने के लिए उत्पादन कम करने का वाणिज्यिक निर्णय लिया है। तथापि, साथ ही, वह यह भी दावा कर रहा है कि अर्थक्षम बने रहने के लिए उसे क्षमता उपयोग 80- 90% की रेंज में बनाए रखना होगा। ये अनुरोध परस्पर विरोधाभासी हैं।

डड. संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में घटा है और वास्तव में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

चच. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री क्षति अवधि के दौरान दोगुनी हो गई है।

छछ. बाजार हिस्से में कमी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा क्षमता विस्तार के कारण हुई। 2020-21 और 2021-22 के बीच आयातों की बाजार हिस्सेदारी में कोई भी वृद्धि मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण हुई और जब घरेलू उत्पादकों ने अपनी क्षमता बढ़ाई तो आयातों ने अपना बाजार हिस्सा खो दिया।

जज. घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

झझ. घरेलू उद्योग और आयात की कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है। जबकि कुवैत से संबद्ध आयातों की कीमतें 2020-21 में 100 सूचकांक से बढ़कर 2021-22 में 142 हो गईं, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता खराब हो गई। यदि आयात कीमत ह्रास और क्षति के लिए जिम्मेदार थे, तो आयात कीमतों में वृद्धि के साथ लाभप्रदता में वृद्धि होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अवधि में बेहतर हुई है, जब कुवैत से कीमतें गिर गईं और संबद्ध सामानों को कथित तौर पर 60-70% तक के उच्च मार्जिन पर पाटित किया जा रहा था, जो सहसंबंध ना होने की पुष्टि करता है।

ञञ. लाभप्रदता मापदंडों में परिवर्तन घरेलू उद्योग की बिक्री की बढ़ी हुई लागत के कारण है। बढ़ती लागत संरचना घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार गिरावट के साथ मेल खाती है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव के बजाय बिक्री लागत लाभप्रदता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है।

टट. घरेलू उद्योग अपने ईथेन का आयात अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरआईएल यूएसए इंक से करता है। जिस कीमत पर घरेलू उद्योग

आरआईएल यूएसए इंक से ईथेन खरीदता है, वह अमेरिका से ईथेन की निर्यात कीमत से बहुत अधिक है।

ठठ. घरेलू उद्योग का यह स्पष्टीकरण कि अंतर बिक्री की शर्तों के कारण था, अर्थात, अमेरिकी कीमतें एफओबी आधार पर रिपोर्ट की गई थीं, जबकि भारतीय आयात कीमतें एफओबी आधार पर रिपोर्ट की गई थीं, गलत है। इतने अधिक अंतर को माल ढुलाई और बीमा के कारण नहीं माना जा सकता। आवेदक की ईथेन की लागत कृत्रिम रूप से अधिक है और इसलिए, प्राधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या आवेदक द्वारा ईथेन की खरीद निकटतम स्तर पर की गई है।

डड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अपनी संबद्ध कंपनी से ईथेन का आयात शुरू करने के बाद से उल्लेखनीय गिरावट आई है और उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि आयात की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी के लिए उपर्युक्त तथ्य जिम्मेदार क्यों नहीं थे।

ढढ. अचल संपत्तियों, नियोजित पूंजी और कार्यशील पूंजी में किसी भी बदलाव के बिना पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का मूल्यह्रास काफी बढ़ गया है। मूल्यह्रास में अचानक वृद्धि के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

णण. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में 2022-23 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लाभप्रदता में सुधार घरेलू उद्योग के बिगड़ती क्षति के दावों के विपरीत है।

तत. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूओआई में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा करना अनुचित है क्योंकि वे विशेष रूप से क्षति रहित कीमत के निर्धारण के संदर्भ में कैप्टिव इनपुट के व्यवहार से संबंधित थे, जो आयात कीमतों के साथ तुलना के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक निर्मित, मानक बेंचमार्क है।

थथ. लाभप्रदता एक सैद्धांतिक निर्माण नहीं है, और कृत्रिम रूप से घाटे को दिखाने के लिए वास्तविक लागतों को काल्पनिक बाजार कीमतों से

प्रतिस्थापित करना क्षति मूल्यांकन की अखंडता को कमजोर करता है और घरेलू उद्योग के वास्तविक आर्थिक निष्पादन को विकृत करता है।

दद. प्राधिकारी को बाहरी बेंचमार्क के आधार पर कोई काल्पनिक समायोजन किए बिना अपनी बहियों में घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए वित्तीय आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि एमईजी उत्पादक आमतौर पर एथिलीन का उत्पादन अपने देश में करते हैं या इसे कैप्टिव व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

धध. उत्पादन की लागत घरेलू उत्पादकों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, न कि काल्पनिक लागतों पर।

नन. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति भौगोलिक कारकों के कारण है, कथित पाटन के कारण नहीं।

पप. आरआईएल ने अपनी हालिया प्रेस विज्ञप्ति में स्वीकार किया है कि उसके एमईजी मार्जिन में निम्न आधार से 46% सुधार हुआ है। तदनुसार, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।

फफ. जबकि अंतिम मालसूची में वृद्धि हुई है, बिक्री की औसत मालसूची दिनों में गिरावट आई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मालसूची सूचकांक में वृद्धि बिक्री में कमी के कारण नहीं, बल्कि निचले स्तर के प्रतिस्पर्धियों को आपूर्ति रोकने के आरआईएल के वाणिज्यिक निर्णय के कार्यनीतिक स्टॉकिंग के कारण हुई है।

बब. उत्पादकता मापदंडों में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत में कमी और निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई।

भभ. घरेलू उद्योग स्वयं एक बहु-उत्पाद कंपनी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पूंजी जुटाने की उसकी क्षमता किसी भी तरह से प्रभावित हुई है।

मम. वास्तविक क्षति का खतरा स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न होना चाहिए। केवल अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी या तीसरे देश के बाजारों में

परिवर्तन अपर्याप्त हैं और वास्तविक क्षति के खतरे का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

यय. इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया है कि भारत निर्यात के लिए पसंदीदा गंतव्य होगा। बीआईएस प्रमाणन आवश्यकताओं की उपस्थिति आयात पर अतिरिक्त शर्तें लगाती है, जिससे बाज़ार तुलनात्मक रूप से कम सुलभ हो जाता है।

ककक. ऐतिहासिक व्यापार पैटर्न भी भारत में अनियंत्रित उछाल नहीं दिखाते हैं, भले ही संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार हुआ हो।

खख. सऊदी अरब से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात भारत को उनके कुल निर्यात के 5% से अधिक नहीं रहा है।

गगग. केवल इसलिए कि संबद्ध देशों में उच्च निर्यात क्षमता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे सामानों का निर्यात किया जाएगा क्योंकि यह कच्चे माल, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं जैसे कारकों पर निर्भर है।

घघघ. घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन मुख्य रूप से बाजार-संचालित कारकों से प्रभावित रहा है, जिसमें कच्चे माल की बढ़ती लागत, मालसूची के स्तर में वृद्धि और वैश्विक अति-आपूर्ति की स्थिति शामिल है, जिसने कीमत वसूली को बाधित किया है और लाभप्रदता को प्रभावित किया है।

डडड. आरआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी दूसरी तिमाही के निवेशक प्रस्तुति में कहा है, "एमईजी-नेफ्था मार्जिन 53% बढ़कर 67 अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी हो गया, जो निचले स्तर के प्रचालनों में वृद्धि और नेफ्था की कमजोर कीमतों के कारण हुआ। हालांकि, क्षमता में अधिकता और अधिक मालसूची के कारण मार्जिन कमजोर बना हुआ है।"

चचच. चीन में आर्थिक मंदी के कारण चीन में एमईजी की खपत कम हुई है, जिससे एमईजी मार्जिन प्रभावित हुआ है, जिसे आरआईएल ने अपने वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही के मीडिया विज्ञप्ति में भी स्वीकार किया था।

छछछ. आवेदक की बिक्री में गिरावट आयात से प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, बल्कि अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई। यदि आयात क्षति का कारण होता, तो सभी भारतीय उत्पादकों की बिक्री में गिरावट होती।

जजज. एमईजी का उत्पादन नेफ्था-व्युत्पन्न एथिलीन पर बहुत अधिक निर्भर है। आरआईएल ने अपने निवेशक प्रस्तुतीकरण में स्वीकार किया है कि नेफ्था की मजबूत कीमतों के कारण एमईजी डेल्टा कम रहा। इस प्रकार, लाभप्रदता में गिरावट बढ़ती इनपुट लागत के कारण है, न कि आयात द्वारा कीमत न्यूनीकरण के कारण।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध</u>

60. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं;

क. भारतीय मांग में वृद्धि ने इसे संबद्ध सामानों के निर्यात के लिए अत्यधिक आकर्षक लक्ष्य बना दिया है। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने बाजार में प्रवेश करने के लिए अपनी कीमतों में आक्रामक रूप से कमी की है। परिणामस्वरूप, भारतीय घरेलू उद्योग 2019 से लगातार पाटित आयातों से क्षति का सामना कर रहा है।

ख. क्षति मापदंडों से संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में, घरेलू उद्योग ने सभी आवश्यक सत्यापन के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसकी आवश्यकता प्राधिकारी को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की सत्यता और शुद्धता का पता लगाने के लिए हो सकती है।

ग. घरेलू उद्योग को 2019 से पाटित एमईजी आयातों से क्षति का सामना करना पड़ रहा है। संबद्ध देश अपने उत्पादन की केवल ***% घरेलू स्तर पर खपत करते हैं और मुख्य रूप से निर्यात पर केंद्रित हैं। जबकि क्षति की अवधि में भारतीय मांग में ***% की वृद्धि हुई, वैश्विक एमईजी खपत में केवल ***% की वृद्धि हुई, जिससे 2024 में संबद्ध देशों की 20% क्षमताएँ निष्क्रिय रह गईं - जो भारत की मांग के ***% के बराबर है।

घ. आईओसीएल के दो संयंत्र पानीपत (क्षमता 457000 एमटी) और पारादीप (क्षमता 357000 एमटी) में स्थित हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की जांच अवधि के अंत में, भारतीय एमईजी क्षमता 27 लाख एमटी हो गई और यह संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ङ. 28 जून, 2021 की अधिसूचना संख्या 6/8/2021-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई पूर्व जांच के बावजूद, जिसमें पाटन और काफी क्षति मार्जिन की पुष्टि की गई थी, कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया क्योंकि घरेलू उद्योग को उचित लाभ अर्जित करने वाला माना गया था और उसे क्षति नहीं हो रही थी।

च. जनवरी 2019 से जारी पाटन और क्षति के बावजूद उपचारात्मक उपायों के अभाव के कारण भारतीय घरेलू उद्योग की स्थिति काफी खराब हो गई है, जो समय के साथ तेज हो गई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है, और उसे गैर-लाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप पीबीआईटी और आरओसीई में लगभग ***% की गिरावट आई है।

छ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से और भारत के उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है, । इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आयात दोगुना हो गया है।

ज. संबद्ध देशों से पाटित आयात भी 2022-23 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन और कुल गैर-कैप्टिव खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

झ. संबद्ध देशों से आयात 2022-23 तक क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में आयात में मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह केवल जून 2023 में एमईजी आयातों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होने के कारण हुआ, जिसने घरेलू उद्योग को केवल अस्थायी राहत प्रदान की। उल्लेखनीय रूप से, जांच की अवधि के बाद की अवधि में, संबद्ध देशों से आयात पहले ही 2022-23 के स्तर को पार कर गया है।

ञ. संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में अधिक रही। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में लगभग ***% से जांच की अवधि में ***% तक तेजी से घटी है।

ट. संबद्ध देशों से आयात 2020-21 से मांग-आपूर्ति के अंतर से अधिक रहा है। जांच की अवधि की चौथी तिमाही में आईओसीएल की क्षमता के चालू होने तक, मांग-आपूर्ति का अंतर 3,00,000-5,00,000 एमटी के बीच था। हालाँकि, संबद्ध देशों से पाटित आयातों का स्तर मांग-आपूर्ति के अंतर से कहीं अधिक था।

ठ. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान और न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, ऐसे आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ड. संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम था, जो स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव को दर्शाता है।

ढ. एसएबीआईसी समूह ने पिछली जाँच की प्रवृत्तियों के आधार पर काल्पनिक परिकलनों पर भरोसा करते हुए आरोप लगाया है कि वर्तमान जांच की अवधि में संबद्ध देशों से कीमत कटौती नकारात्मक है। केवल अनुमान पर कोई भार नहीं डाला जाना चाहिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहाँ वास्तविक सत्यापित आंकड़े प्राधिकारी के पास आसानी से उपलब्ध हैं।

ण. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ऐतिहासिक रूप से, 2018-19 से क्षमता उपयोग ***% से ऊपर रहा है, लेकिन निरंतर पाटन के कारण, यह ***% से नीचे गिर गया है, जिससे उत्पादन गैर-अर्थक्षम हो गया है। उत्पादन ने जांच की अवधि में उल्लेखनीय गिरावट की इस प्रवृत्ति को दर्शाया है।

त. 2020-21 और 2022-23 के बीच मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री में गिरावट आई। यद्यपि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होने के कारण जांच की अवधि में मामूली सुधार हुआ, जांच की अवधि के दौरान बिक्री का स्तर आधार वर्ष की तुलना में ***% कम रहा। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात लगभग दोगुना हो गया।

थ. जांच की अवधि को छोड़कर, संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा लगातार बढ़ा, जिसमें यह 2022-23 के स्तर की तुलना में थोड़ा कम हुआ, लेकिन आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में अधिक रहा।

द. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में लगभग 50% से घटकर जांच की अवधि में 30% हो गया।

ध. जांच की अवधि में मामूली सुधार के बावजूद, बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से काफी नीचे रही है।

न. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति की 2018-19 की अवधि (अर्थात वह अवधि जब कोई पाटन नहीं था) के साथ तुलना करने पर घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, निवेश पर आय और लाभ में उल्लेखनीय गिरावट दिखाई देती है।

प. लाभप्रदता के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बहीखातों पर आधारित है, जो एक एकीकृत निर्माता है जिसे कैप्टिव एथिलीन के कारण लागत लाभ प्राप्त है। उल्लेखनीय रूप से, प्रमुख कच्चा माल, एथिलीन, आरआईएल के बहीखातों में लागत पर अंतरित किया गया है। माननीय सेस्टैट ने 29.09.2023 के अपने निर्णय में, *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (2006 (202) ई.एल्टी 23 (एस.सी.))* में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए निर्णय सुनाया कि क्षति के आकलन में कैप्टिव इनपुट की बाजार कीमत पर विचार किया जाना चाहिए, न कि आंतरिक अंतरण कीमतों पर। यदि एथिलीन की बाजार कीमतों को शामिल किया जाए तो आरआईएल का सीमांत लाभ घाटे में बदल जाएगा।

फ. सभी वित्तीय मापदंडों, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ, आरओसीई और पीबीडीआईटी में 2020-21 से उल्लेखनीय गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को 2022-23 के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा। जांच की अवधि में आंशिक सुधार क्यूसीओ के कारण अस्थायी राहत के कारण हुआ।

ब. आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में, घरेलू उद्योग के सभी लाभप्रदता मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

भ. एसएबीआईसी समूह ने चुनिंदा रूप से अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, जबकि घरेलू उद्योग के ईथेन की कथित आयात कीमतों का खुलासा करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जो उसके दावे का आधार है।

म. घरेलू उद्योग ने ऑन-साइट सत्यापन के दौरान जांच दल के साथ पूरा सहयोग किया है और आरआईएल यूएसए के माध्यम से ईथेन की कीमतों की खरीद के संबंध में सभी वांछित सूचना प्रदान की है, जो स्पष्ट रूप से एसएबीआईसी समूह द्वारा किए गए झूठे विवरण को खारिज करता है।

य. आरआईएल, आरआईएल यूएसए के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं से सीधे ईथेन खरीदता है। विगत में भी, आरआईएल इंडिया ने उन व्यापारियों से एथेन प्राप्त किया है जो ट्रेडिंग मार्जिन लेते थे। यही मार्जिन आरआईएल यूएसए को सोर्सिंग के खर्च के रूप में दिया जाता रहा है। एथेन खरीद कीमत का मानकीकरण उसी मानक के अनुसार किया जाता है जो पहले असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था।

कक. घरेलू उद्योग एथिलीन का निजी तौर पर निर्माण करता है और उसे लागत पर अंतरित करता है। चूँकि एथिलीन लागत पर अंतरित होता है, इसलिए यह बाजार में उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं होता है।

खख. एथिलीन की बाजार कीमत को लागू करने से एथेन की कथित बढ़ी हुई कीमत और उसके परिणामस्वरूप एथिलीन की कीमतों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का समाधान हो जाएगा।

गग. बढ़ती घरेलू माँग के बावजूद, निरंतर पाटन और क्षति के कारण, किसी भी नई घरेलू क्षमता की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि मौजूदा क्षमताएँ अभी भी कम उपयोग में हैं।

घघ. एमईजी, आरआईएल के अंतर्गत एक कार्य-नीतिक व्यावसायिक इकाई है और एमईजी से संबंधित सभी निवेश, जिसमें भविष्य में पूंजी निवेश जुटाना भी शामिल है, एमईजी व्यवसाय की लाभप्रदता और उससे अर्जित आय के आधार पर तय किए जाते हैं। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्वीकार कर लिया जाए, तो इसका अर्थ यह होगा कि सभी बहु-उत्पाद कंपनियों को लाभदायक व्यावसायिक क्षेत्रों से धन घाटे वाले क्षेत्रों में लगाना चाहिए।

डड. इक्वेट ग्रुप ने आरआईएल की निवेशक प्रस्तुति का हवाला देते हुए दावा किया है कि वैश्विक अतिक्षमता के कारण आरआईएल की लाभप्रदता में गिरावट आई है। संबद्ध देशों में अत्यधिक क्षमता और उनके संबंधित बाजारों में लगभग शून्य घरेलू खपत के कारण, संबद्ध देशों के निर्यातकों ने उच्च एमईजी खपत वाले एकमात्र शेष बाजार, अर्थात भारत को ही लक्ष्य बनाया है।

चच. संबद्ध देशों के उत्पादक मुख्यतः निर्यातोन्मुख हैं और अपने घरेलू बाजार की खपत के संबंध में महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता बनाए रखते हैं, जिससे भारतीय घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है।

छछ. संबद्ध देशों में घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं स्थापित की गई हैं। ये क्षमताएं संपूर्ण भारतीय मांग का लगभग ***% हैं।

जज. संबद्ध देशों के बाजारों में संबद्ध सामानों की खपत और उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर है। यह संभावना नहीं है कि संबद्ध देशों के संबद्ध सामानों के निर्यातक अपने निर्यात को तीसरे देशों में भेज पाएंगे।

झझ. संबद्ध देशों में से एक (सऊदी अरब) से यूरोपीय संघ को संबद्ध सामानों का निर्यात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण प्रतिबंधित है। इसके

अलावा, चीन में बढ़ी हुई स्वदेशी क्षमता के कारण चीन का बाजार भी अब उपलब्ध नहीं है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

61. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *पाटित आयातों की मात्रा, समान सामानों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए"* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर विचार किया गया है।

62. प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैराग्राफों में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है।

ज.3.1 क्षति का संचयी आकलन

63. विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि किसी उत्पाद का एक से अधिक देशों से आयात एक साथ पाटनरोधी जाँच के अधीन हो रहा है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान एक-दूसरे की समान वस्तु हैं और प्रयोक्ता उद्योग ने एक या अधिक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर खंड ग में उल्लेख किया गया है, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान वस्तु भी हैं।

ख. जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के खंड छ में निर्धारित किया गया है, संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं और पाटन मार्जिन पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ग. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।

घ. संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान सामानों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

65. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि आयातों के संचयी मूल्यांकन हेतु निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हैं और उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी मूल्यांकन किया है।

66. क्षति मूल्यांकन हेतु ईरान को शामिल करने के संबंध में आयातक एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा पाटनरोधी नियमावली में निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से कम थी। तदनुसार, ईरान को वर्तमान जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

68. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में संबद्ध सामानों की कुल माँग को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर सभी स्रोतों से संबद्ध सामानों के आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकित माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
संबद्ध देश	एमटी	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	173	248	200
कुवैत	एमटी	3,83,519	6,16,079	7,85,939	7,14,900
सऊदी अरब	एमटी	1,24,417	2,31,913	4,11,242	3,06,948
सिंगापुर	एमटी	20,592	64,583	1,15,332	35,739
गैर-संबद्ध देशों से आयात	एमटी	44,878	9,424	74,336	15,586
कुल आयात	एमटी	5,73,407	9,21,998	13,86,849	10,73,172
घरेलू उद्योग की कुल बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	100	93
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	84	156
कैप्टिव सहित कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	135	122

कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	132	145	135

69. यह नोट किया जाता है कि:

क. संबद्ध सामानों की मांग 2022-23 तक लगातार बढ़ी है। 2022-23 की तुलना में जांच अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई है। तथापि, मांग 2021-22 और 2022-23 के स्तर से ऊपर बनी हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान, मांग में ***% की वृद्धि हुई है।

ख. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में, जांच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई है, जबकि 2022-23 की तुलना में, जांच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा और पाटित आयात का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
कुवैत	एमटी	3,83,519	6,16,079	7,85,939	7,14,900
सऊदी अरब	एमटी	1,24,417	2,31,913	4,11,242	3,06,948
सिंगापुर	एमटी	20,592	64,583	1,15,332	35,739
संबद्ध देश	एमटी	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
गैर-संबद्ध देश	एमटी	44,878	9,424	74,336	15,586

कुल आयात	एमटी	5,73,407	9,21,998	13,86,849	10,73,172
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
कैप्टिव खपत के बिना मांग	%	36%	46%	61%	53%
उत्पादन	%	31%	55%	89%	78%
कुल आयात	%	92%	99%	95%	99%

71. उपर्युक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि-

क. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, फिर भी यह नोट किया जाता है कि ऐसे आयात आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से काफी ऊपर बने हुए हैं।

ख. संबद्ध देशों से संबद्ध आयात भारत में कुल आयातों का लगभग पूरा हिस्सा थे, जो जांच की अवधि के दौरान 99% का पर्याप्त हिस्सा दर्शाते हैं।

ग. आधार वर्ष की तुलना में, भारतीय मांग और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में क्रमशः ***% और ***% की वृद्धि हुई है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में, जांच की अवधि में भारतीय मांग और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, फिर भी वे आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से काफी ऊपर बने हुए हैं।

घ. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 तक, मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात आवश्यक थे और एमईजी के लिए आईओसीएल की विस्तारित क्षमता के प्रचालनीकरण के साथ, जांच की अवधि में आयात में गिरावट आई है, जो घरेलू सोर्सिंग की ओर परिवर्तन का संकेत देता है, जो दर्शाता है कि

आयात का कोई निरंतर दबाव नहीं है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि भारत सरकार द्वारा क्यूसीओ लागू करने के कारण जांच की अवधि में आयात में अस्थायी रूप से गिरावट आई है।

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईओसीएल की क्षमता में वृद्धि के बावजूद, जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात 2021-22 और आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बना हुआ है। आईओसीएल ने संबद्ध सामानों के लिए दो चरणों में क्षमता विस्तार किया है - पहला क्षमता विस्तार 2022-23 में हुआ, जिसमें इसके पानीपत संयंत्र में एमईजी क्षमता पहले के 3,02,000 एमटी से बढ़ाकर 425,000 एमटी कर दी गई थी। दूसरा क्षमता विस्तार जांच की अवधि के अंत में हुआ, जिसमें इसके पारादीप संयंत्र में 332,000 एमटी के साथ एक नए एमईजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 2021-22 और जांच की अवधि के बीच, आईओसीएल की क्षमता में लगभग 1,20,000 एमटी की वृद्धि हुई। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयात में भी 1,45,011 एमटी की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि आईओसीएल द्वारा क्षमता विस्तार के कारण संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा में गिरावट आई।

74. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी दावा किया है कि भारतीय मांग में वृद्धि के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध आयात में गिरावट आई है, और इसलिए, क्षति को संबद्ध देशों से संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि जांच अवधि में मांग 2022-23 के स्तर की तुलना में कम हुई है, फिर भी जांच अवधि में मांग का स्तर 2021-22 के स्तर से ऊपर और तुलनीय बना हुआ है।

75. यह नोट किया जाता है कि 2021-22 और जांच अवधि के बीच, जबकि मांग में केवल ***% की वृद्धि हुई, संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में 16% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, भारतीय उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री में ***% की गिरावट आई। आधार वर्ष की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि जांच अवधि में मांग में निरपेक्ष वृद्धि से अधिक रही है। यह दर्शाता है कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों से असहमत हैं।

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से काफी मात्रा में आयात किया है। जैसा कि ऊपर पहले ही जांच की जा चुकी है, यह नोट

किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया आयात उसके कुल उत्पादन और बिक्री का केवल लगभग 1% है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

77. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार कीमतों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक अन्यथा कीमत ह्रास करने के लिए है या कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क) कीमत कटौती

78. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के आधार पर संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।

कीमत कटौती					
संबद्ध देश	**सीआईएफ मूल्य**	**पहुंच मूल्य**	**एनएसआर**	**कीमत कटौती**	**कीमत कटौती रेंज**
	रु./एमटी	**रु./एमटी**	**रु./एमटी**	**%**	**रेंज**
कुवैत	41,574	43,860	***	***	0-10
सऊदी अरब	41,952	44,260	***	***	0-10
सिंगापुर	42,988	44,171	***	***	0-10
संबद्ध देश	41,731	43,987	***	***	0-10

79. जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, संबद्ध देशों के मूल के संबद्ध सामान घरेलू उद्योग के एनएसआर से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात किए गए थे।

संबद्ध देशों से कीमत कटौती समग्र रूप से और प्रत्येक संबद्ध देश से सकारात्मक है।

80. एसएबीआईसी समूह ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई कीमत कटौती परिकलन पर विवाद किया है और दावा किया है कि केएसए की तुलना में कीमत कटौती नकारात्मक है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक निवल बिक्री प्राप्ति पर विचार किया है जिसके आधार पर उन्होंने केएसए के लिए कीमत कटौती को सकारात्मक निर्धारित किया है।

81. एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि कीमत कटौती पर विचार करते समय केवल गैर-कैप्टिव बिक्री पर ही विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा एमईजी को कैप्टिव और गैर-कैप्टिव खपत के लिए बाजार कीमत पर अंतरित किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने कटौती के परिकलन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा की गई सभी घरेलू बिक्री के लिए निवल बिक्री प्राप्ति पर विचार किया है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

82. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आवेदकों ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू निवल बिक्री प्राप्ति के बारे में सूचना प्रदान की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। इसकी तुलना संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य से की गई है।

कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	187	142
पहुंच कीमत	रु./एमटी	39,064	53,481	46,402	43,987
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	119	113
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	126	119

83. यह देखा जाता है कि वर्ष 2021-22 तक, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत बढ़ी और आवेदक की बिक्री लागत से ऊपर रही। घरेलू उद्योग वर्ष 2021-22 तक अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के साथ-साथ अपनी बिक्री कीमत में भी वृद्धि करने में सक्षम रहा। तथापि, वर्ष 2022-23 से, संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य लगातार कम हुआ है, जिसके साथ ही संबद्ध सामानों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि उसे अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए आयात कीमतों के बराबर कीमत रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग का एनएसआर भी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत के समान ही रहा है। इस प्रकार, पहुँच कीमत में गिरावट ने घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बने रहने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अपने एनएसआर को कम करने के लिए मजबूर किया।

84. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लागत स्तर पर बिक्री कर रहा है और मुश्किल से कोई लाभ कमा रहा है, जबकि जांच की अवधि में उसकी बिक्री लागत में कमी आई है।

85. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष से ऊपर की ओर बढ़ी है, अत: यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों में तद्नरूपी वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमतों में गिरावट आई है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है।

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी टिप्पणी की है कि चीन में कीमतों में गिरावट के कारण जांच की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर संबद्ध सामानों की कीमतों में गिरावट आई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने वैश्विक कीमतों में गिरावट को प्रमाणित करने वाली कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इसके विपरीत, एसओके और केएसए के प्रतिभागी निर्यातकों, जो वैश्विक स्तर पर विचाराधी उत्पाद के प्रमुख निर्यातक हैं, द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों को निर्यात कीमतें वास्तव में 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी हैं। तदनुसार,

यह नहीं माना जा सकता कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय बाजार में कीमतें घटी हैं।

ञ.1 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

87. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह; मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होने चाहिएं। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

88. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

उत्पादन, संस्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	86	80
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रेंज	%	90-100%	90-100%	80-90%	80-90%
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	100	93

89. उपर्युक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। तथापि, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इसी अवधि में लगातार कम होता गया और जांच की अवधि के दौरान अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गया।

ख. घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री के साथ-साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

90. एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने वास्तविक प्रकार्यात्मक क्षमता से अधिक क्षमता की सूचना दी है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई क्षमता का सत्यापन किया है और पाया है कि यह सही ढंग से दी गई है।

91. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जांच की अवधि के दौरान बिक्री में गिरावट कैप्टिव खपत में कमी और निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई। प्राधिकारी ने पिछले कुछ वर्षों में घरेलू उद्योग द्वारा की गई कैप्टिव बिक्री और गैर-कैप्टिव बिक्री की मात्रा की तुलना की है। यह नोट किया जाता है कि कुल बिक्री में कैप्टिव और मुक्त बाजार बिक्री के बीच का अनुपात क्षति अवधि के दौरान समान श्रेणी में रहा है। यह नोट किया जाता है कि 2022-23 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री में कुछ मामूली सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा जांच अवधि के दौरान क्यूसीओ लागू होने के कारण हुआ है।

92. निर्यात बिक्री में गिरावट के संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि निर्यात बिक्री आधार वर्ष और 2021-22 के दौरान की गई क्योंकि केएसए, एसओके और यूएसए द्वारा बेचे जा रहे पाटित और कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू बाजार की कीमतें लाभप्रद नहीं थीं।

ख) बाजार हिस्सा

93. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

बाजार हिस्सा					
बाजार हिस्सा	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की**

					अवधि
घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	85	87
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	84	156
कुल भारतीय बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	85	102
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	5,28,528	9,12,575	13,12,512	10,57,586
अन्य देशों से आयात	एमटी	44,878	9,424	74,336	15,586
भारत में गैर-कैप्टिव मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	एमटी	100	132	145	135
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
अन्य देश का आयात	%	***	***	***	***

94. यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में ***% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में ***% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर बिक्री करके घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर रहे हैं।

95. यह नोट किया जाता है कि 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, तथापि, संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से ऊपर बनी हुई है।

96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की गैर-कैप्टिव बिक्री 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा जांच अवधि के दौरान क्यूसीओ लगाए जाने के कारण हुआ है। इसके अलावा, 2021-22 की तुलना में, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई समग्र गिरावट के संबंध में काफी नहीं थी और संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

97. इसके अतिरिक्त, 2021-22 अर्थात्, वह अवधि जिसमें मांग का स्तर जांच की अवधि के समान था, से तुलना करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वास्तव में गिरावट आई है, जबकि जांच की अवधि में संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण सामूहिक रूप से बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

ग) मालसूची

98. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

मालसूची					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	87	98

99. यह नोट किया जाता है कि 2022-23 तक मालसूची में गिरावट आई, जिसके बाद इसमें वृद्धि हुई और यह लगभग आधार वर्ष के स्तर पर पहुँच गई।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

100. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

लाभप्रदता मापदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	187	142
एनएसआर	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	126	119
पीबीटी	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	(170)	5
पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	(104)	25
पीबीडीआईटी	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	(44)	60
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	(***)	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	(69)	56
नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में पीबीआईटी (आरओसीई)	%	***	***	(***)%	***
रेंज	%	0-10	0-10	(10)-0	0-10

101. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

क. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2021-22 और 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में 2022-23 तक काफी गिरावट आई, जिसके बाद मामूली सुधार देखा गया। आवेदक ने

अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने विचाराधीन उत्पाद पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया था। फलस्वरूप, आयात में आंशिक कमी आई, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में थोड़ा सुधार हुआ, जिसके दौरान घरेलू उद्योग को काफी हानियां हुई थीं।

ग. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि क्यूसीओ लागू करना घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए एक व्यापक उपाय नहीं है, क्योंकि अधिकतर निर्यातकों ने भारत को निर्यात जारी रखने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। परिणामस्वरूप, यद्यपि कयूसीओ के कारण आयात में अस्थायी रूप से बहुत कम कमी आई हो सकती है, यह कम कीमतों पर आयात के मूलभूत मुद्दे का समाधान नहीं करता है, जो घरेलू उद्योग के निष्पादन पर दबाव बना रहा है।

102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा 2022-23 से अपने संबद्ध पक्षकार, आरआईएल यूएसए इंक. से ईथेन की खरीद के कारण है। यह भी उल्लेख किया गया है कि बाजार आसूचना के माध्यम से रिपोर्ट की गई आरआईएल की ईथेन की खरीद कीमत, अमेरिका से ईथेन की निर्यात कीमत से काफी अधिक है। इसकी जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए ईथेन के खरीद बीजक मांगे। इसकी जांच के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की ईथेन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं और घरेलू उद्योग 2022-23 से पहले अन्य असंबद्ध स्रोतों से खरीद के लिए समान मानक का उपयोग कर रहा था। कमीशन और अन्य प्रभार भी उसी रेंज में है। मूल्यह्रास में परिवर्तन के संबंध में, प्राधिकारी ने उसका सत्यापन किया है और जहाँ भी आवश्यक हुआ, उचित समायोजन किया गया है।

103. इक्वेट ग्रुप ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट और पहुँच मूल्य के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि 2021-22 में पहुँच मूल्य में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020-21 और 2021-22 के बीच, घरेलू उद्योग पहुँच मूल्य में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा। हालाँकि, संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ा। तदनुसार, घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई।

104. अन्य हित पक्षकारों ने भी आरआईएल की निवेशक प्रस्तुति का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं, बल्कि वैश्विक अतिक्षमता के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेशक प्रस्तुतियाँ शेयरधारकों के लिए समेकित कारपोरेट संचार होती हैं, जबकि क्षति परीक्षण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सत्यापित उत्पाद-विशिष्ट लागत आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, निवेशक प्रस्तुतियों में दिए गए पृथक विवरण क्षति के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में निर्धारक नहीं होते हैं।

ड.) रोज़गार, उत्पादकता और मजदूरी

105. घरेलू उद्योग के रोज़गार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

श्रम और उत्पादकता मापदंड					
विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	96	95
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	80	92
उत्पादकता/दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	86	80

106. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या और उनकी मजदूरी में कमी आई है।

107. घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है।

च) वृद्धि

वृद्धि				
विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**POI**	**आधार वर्ष के संबंध में**
उत्पादन	(***)%	(***)%	(***)%	(***)%
घरेलू बिक्री	(***)%	(***)%	***%	(***)%
लाभ	(***)%	(***)%	***%	(***)%
आरओसीई	(***)%	(***)%	***%	(***)%

108. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में घरेलू उद्योग के लाभ में काफी गिरावट आई है। यद्यपि, 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में आरओसीई से संबंधित आंकड़ों में सुधार देखा गया है, फिर भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में आरओसीई में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

109. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि वह लाभ पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाया है और इसलिए, पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता में काफी कमी आई है। यह भी दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश करने की योजना नहीं बनाई जा रही है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेश पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाए हैं।

ज) पाटन की मात्रा

110. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और इसे काफी माना जाता है।

111. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ञ.2. वास्तविक क्षति का खतरा

112. वास्तविक क्षति के अपने दावे के अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात से घरेलू उद्योग को और अधिक

वास्तविक क्षति होने का खतरा है। आवेदकों ने संबद्ध देशों की खपत, उत्पादन और बिक्री के संबंध में पीसीआई वुडमैकेंज़ी पर आधारित आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।

संबद्ध देशों में उत्पादन, मांग और क्षमताएं				
विवरण	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
संबद्ध देशों का उत्पादन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	112	111	113
संबद्ध देशों की क्षमताएं	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	105	105	105
बेकार क्षमताएँ	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	80	82	77
संबद्ध देशों की मांग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	104	101	106
भारतीय मांग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	123	135	122
भारतीय मांग के % के रूप में बेकार क्षमता	***	***	***	***
रेंज	110-120	70-80	70-80	70-80

स्रोत: पीसीआई वुड मैकेंज़ी रिपोर्ट

113. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों ने 2021 से 2024 की अवधि के दौरान काफी बेकार क्षमताएँ बनाए रखी हैं। यद्यपि बेकार क्षमताओं में 2021 में *** एमटी से 2024 में *** एमटी तक आंशिक गिरावट आई है, फिर भी ऐसी बेकार क्षमताएँ पर्याप्त बनी हुई हैं। संबद्ध देशों में घरेलू माँग उनकी क्षमताओं की तुलना में नगण्य है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों में 95% से अधिक उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं से अधिक है, जिससे वे संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख बन जाते हैं। बढ़ती

भारतीय माँग, संबद्ध देशों में नगण्य घरेलू माँग के साथ, भारत को संबद्ध देशों के अधिशेष उत्पादन के लिए एक स्वाभाविक आधार बनाती है।

114. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों के प्रमुख बाजारों में से एक, चीन ने भी एमईजी के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और तदनुसार, निर्यात संबद्ध देशों से भारत को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा उनके व्यक्तिगत प्रश्नावली उत्तर के अनुबंध-1 में प्रदान की गई मात्रात्मक सूचना की भी जांच की है। कुवैत के मामले में, प्राधिकारी नोट करते है कि संबद्ध सामानों का उत्पादन 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ा है, और भारत को निर्यात बिक्री भी बढ़ी है और जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में तीसरे देशों को निर्यात बिक्री में गिरावट आई है। यह नोट किया जाए कि इन बिक्रियों में इक्वेट समूह द्वारा की गई व्यापारिक बिक्री भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात इक्वेट समूह के कुल उत्पादन का लगभग 53% है।

115. सऊदी अरब के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों ने केवल जांच की अवधि के लिए बाजार-वार बिक्री सूचना प्रदान की है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस जांच के लिए उनके संबंधित व्यापारी एसएबीआईसी द्वारा की गई बिक्री पर विचार किया है। इसके आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और तृतीय देशों को संबद्ध सामानों के निर्यात में कैलेंडर वर्ष 2022 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और फिर कैलेंडर वर्ष 2023 में और वृद्धि हुई, जबकि भारत और तृतीय देशों को निर्यात के लिए जांच की अवधि में आंशिक गिरावट आई। तथापि, क्षति अवधि के दौरान भारत को निर्यात की वृद्धि दर, तृतीय देशों को निर्यात की वृद्धि दर से काफी अधिक रही। उल्लेखनीय है कि भारत को निर्यात में वृद्धि कैलेंडर वर्ष 2022 में हुई, जो यूरोपीय संघ को संबद्ध सामानों के निर्यात के संबंध में एसएबीआईसी समूह पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अवधि के साथ मेल खाती है।

116. आवेदकों ने तीसरे देशों में एमईजी की मांग भी उपलब्ध कराई है।

तीसरे देशों में एमईजी मांग				
विवरण	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
मांग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	99	101	107

117. यह नोट किया जाता है कि भारत की तुलना में तीसरे देशों में मांग अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जहाँ मांग में काफी वृद्धि देखी गई है। बढ़ती भारतीय मांग और संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की वृद्धि दर को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का निर्यात भारतीय बाजार की ओर मोड़ा जाएगा।

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास पर्याप्त अधिशेष और बेकार क्षमताएँ हैं, जो उनकी सीमित घरेलू मांग से कहीं अधिक हैं, जिससे वे संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख बन जाते हैं। बेकार क्षमताएँ ही भारतीय मांग के एक बड़े हिस्से के बराबर हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ द्वारा व्यापार सुधारात्मक उपाय लागू करने के कारण, ऐसे निर्यातों के लिए सीमित बाजार हैं। साथ ही, भारतीय मांग में वृद्धि जारी रही है, जिससे भारत निर्यात के लिए एक आकर्षक लक्ष्य स्थान बन गया है।

ञ.3. क्षति का समग्र मूल्यांकन

119. संबद्ध सामानों के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जाँच से निम्नलिखित पता चलता है:

i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा है। यद्यपि 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट आई, फिर भी जांच अवधि में आयात की मात्रा 2020-21 और 2021-22 की तुलना में काफी अधिक थी।

ii. संबद्ध आयातों का पहुँच मूल्य 2022-23 और जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय रूप से काफी कम हुआ। इस गिरावट के साथ-साथ बड़ी आयात मात्रा ने घरेलू बिक्री कीमतों पर निरंतर गिरावट का दबाव बनाया।

iii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती की है और इसकी बिक्री कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास भी किया है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी लागतों के अनुरूप कीमतें बढ़ाने से रुक गया है।

iv. आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में, मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा में गिरावट आई

है, जो पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उद्योग की उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता को दर्शाता है। यद्यपि, 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के मापदंडों में आंशिक रूप से सुधार हुआ है, फिर भी 2021-22 की तुलना में इसकी बाजार हिस्सेदारी निम्न स्तर पर बनी हुई है, जबकि संबद्ध देशों ने मांग के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

v. घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन काफी खराब हो गया है। लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय 2022-23 में नकारात्मक हो गई। 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में मामूली सुधार हुआ, लेकिन घरेलू उद्योग गैर-लाभकारी आय और लाभ अर्जित कर रहा है।

vi. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

vii. संबद्ध देश अपनी घरेलू मांग से कहीं अधिक बड़ी उत्पादन क्षमता बनाए रखते हैं, जिसमें बेकार क्षमताएं अकेले भारतीय मांग के ***% के बराबर हैं। संबद्ध देशों के उत्पादक संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख हैं।

viii. संबद्ध देशों में पर्याप्त बेकार क्षमता, उन देशों में महत्वपूर्ण घरेलू मांग का अभाव, अन्य प्रमुख बाजारों में प्रतिबंध, तथा बढ़ती भारतीय मांग के संयोजन से यह सिद्ध होता है कि भारत संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए एक स्वाभाविक लक्ष्य है, जिससे आगे और अधिक क्षति का वास्तविक और आसन्न खतरा पैदा हो रहा है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

120. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम

उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय अलग किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III मे निर्धारित क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

121. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।

झ.1. संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

122. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल कंपनी माना गया है और उन्हें एक ही क्षति मार्जिन दिया गया है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई है।

123. ऊपर निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	**क्षति रहित कीमत (डॉ./एमटी)**	**पहुंच कीमत (डॉ./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (डॉ./एमटी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन रेंज**
कुवैत					
इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
कुवैत ओलेफिन्स कंपनी	***	***	***	***	20-30
इक्वेट समूह भारित औसत	***	***	***	***	20-30

अन्य	***	***	***	***	30-40
सऊदी अरब					
अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
एसएबीआईसी समूह भारित औसत	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	30-40
सिंगापुर					
अन्य	***	***	***	***	20-30

ञ. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

124. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की भी जाँच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि अन्य कारकों, यदि कोई हों, से हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध सामानों की मात्रा, माँग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

125. यह नोट किया जाता है कि गैर-संबद्ध देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से नगण्य हैं। संबद्ध देशों से आयात भारत में होने वाले आयात का लगभग 1% है। अत:, हुई क्षति के लिए तृतीय देशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

ख) मांग में संकुचन

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की मांग वित्त वर्ष 2022-23 तक बढ़ी है। जांच की अवधि के दौरान मांग में आंशिक गिरावट आई है। तथापि, मांग का स्तर आधार वर्ष और 2021-22 के स्तर से ऊपर बना हुआ है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

127. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हों।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

130. ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इसलिए, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

131. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ञ.1. कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

132. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, फिर भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

i. प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध आयात न्यूनतम सीमा से ऊपर पाटित किए जा रहे हैं, और संचयी मूल्यांकन उपयुक्त पाया गया है क्योंकि प्रत्येक देश से आयात न्यूनतम मात्रा सीमा से अधिक है।

ii. संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा लगातार उच्च बनी हुई है और 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट के बावजूद, भारत में कुल आयात का 99% हिस्सा है और भारतीय मांग का ***% से अधिक है। 2021-22 और जांच की अवधि के बीच, आयात में ***% की वृद्धि हुई जबकि मांग में केवल ***% की वृद्धि हुई।

iii. घरेलू उद्योग की खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

iv. संबद्ध देशों की पहुँच कीमत एनएसआर से कम है, जिससे जाँच की अवधि में सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।

v. 2022-23 से, संबद्ध देशों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है, जबकि मात्रा उच्च बनी हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के एनएसआर में भी यही गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो कीमत ह्रास/न्यूनीकरण दर्शाता है। जाँच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग को लागत के करीब बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह लागत के अनुरूप कीमतें नहीं बढ़ा सका।

vi. जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ***% था। यद्यपि 2022-23 की तुलना में आंशिक सुधार हुआ है, फिर भी यह 2020-21 और 2021-22 के स्तर से काफी नीचे बना हुआ है।

vii. आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मापदंडों में काफी गिरावट आई है। लाभ ***% से कम हो गया है जबकि आरओसीई ***% तक कम हो गया है।

133. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

134. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एमईजी को शुद्ध टेरेफ्थैलिक अम्ल ("पीटीए") के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसे मेल्ट कहा जाता है, जिसका उपयोग सिंथेटिक यार्न के उत्पादन में किया जाता है। मेल्ट की लागत में एमईजी का योगदान 23.40% है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

ख. 20%-30% पाटनरोधी शुल्क लगाने से एमईजी की कीमतों में 5.10 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होगी। यदि एमईजी पर शुल्क लगाया जाता है, तो भारतीय विनिर्माण उद्योग अपने प्रचालनों का विस्तार नहीं कर पाएगा क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर एमईजी की खरीद नहीं कर पाएगा।

ग. वित्त मंत्रालय ने पीटीए पर शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया था और तदनुसार, पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले शुल्कों को समाप्त कर दिया था।

घ. आवेदक ने कथित 0.3% के प्रभाव की गणना कैसे की गई है, इसका अगोपनीय विवरण प्रदान नहीं किया है। उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में अपेक्षाकृत छोटी लागत वृद्धि, विशेष रूप से कम मार्जिन पर काम करने वाले उद्योगों में, जटिल हो सकती है।

ड. विचाराधीन उत्पाद, पॉलिएस्टर फाइबर, वस्त्र और विभिन्न निचले स्तर के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, और पैकेजिंग, सौंदर्य प्रसाधन और ईवी बैटरी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। भारत का घरेलू उत्पादन अपर्याप्त है, जिसका 70% से अधिक हिस्सा निजी उपयोग में ही कैप्टिव रूप से खपत होता है, जिससे मांग को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक हो जाता है। विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क निचले स्तर

के उद्योगों की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, जिससे पॉलिएस्टर वस्त्र और पीईटी पैकेजिंग अधिक महंगी हो जाएगी, उल्टा शुल्क ढांचा और भी जटिल हो जाएगा और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इससे 40,000 से अधिक छोटे और मध्यम आकार के निर्माताओं पर असर पड़ेगा, नौकरियों पर खतरा मंडराएगा और लिथियम-आयन बैटरी की लागत में वृद्धि के कारण भारत के ईवी लक्ष्यों में बाधा आएगी। कुल मिलाकर, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

च. पाटनरोधी शुल्क लगाने से पूरे टेक्सटाइल क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही कीमत दबाव में है। आवेदक अंतिम उत्पादों के लिए एमईजी का एक बड़ा हिस्सा निजी तौर पर उपयोग करता है, अन्य उत्पादकों को नुकसान होगा, उन्हें आवेदक के साथ प्रतिस्पर्धा करने और महंगा कच्चा माल खरीदते हुए एमईजी का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर ("पीएसएफ") की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि घरेलू उद्योग लगभग पूरी क्षमता से काम कर रहा है, इसके बावजूद उच्च पहुंच लागत और घरेलू आपूर्ति की भारी कमी है। इसके अतिरिक्त, घरेलू एमईजी की कीमतों में पाटनरोधी शुल्क के साथ-साथ वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला में लागत और बढ़ जाएगी। इससे भारतीय पीएसएफ और निचले स्तर के उद्योगों पर सस्ते आयात के कारण पहले से ही पड़ रहा कीमत निर्धारण का दबाव और बढ़ जाएगा, जिससे वे कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, व्यवसाय बंद होने का जोखिम होगा और संभावित रूप से नौकरी छूटने की संभावना होगी। पीएसएफ जैसे कम मार्जिन वाले व्यवसाय के लिए, 100 डॉलर/एमटी का पाटनरोधी शुल्क कच्चे माल की लागत में 2,530 रुपये/एमटी की वृद्धि करेगा, जिससे काफी वित्तीय भार बढ़ेगा और इस क्षेत्र की अर्थ क्षमता को खतरा होगा।

ज. आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू और निर्यात बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। खरीदारों के पास सीमित खरीद विकल्प हो सकते हैं, जिससे पहले से ही आपूर्तिकर्ताओं की कम संख्या के कारण एकाधिकार की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे संकटग्रस्त टेक्सटाइल उद्योग के लिए चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पादकों के बीच भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन की कमी के कारण उत्पाद की उपलब्धता और भी सीमित हो जाती है।

झ. टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चे माल, विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू कीमतें बढ़ेंगी, जिससे टेक्सटाइल यार्न की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इससे माँग कम होगी, उत्पादन दर कम होगी और लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। फलस्वरूप, घरेलू बाजारों में टेक्सटाइल क कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होगी। विचाराधीन उत्पाद की कमी के कारण, घरेलू निर्माता अपनी कीमतें आयातित कीमतों के अनुरूप कर देंगे, जिससे लागत और बढ़ जाएगी।

ट.2 घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध

135. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारतीय एमईजी उद्योग एकाधिकार नहीं है, जैसा कि भारत के दो अन्य महत्वपूर्ण उत्पादकों (आईजीएल और आईओसीएल) और विशेष रूप से, आईओसीएल द्वारा अपनी क्षमताओं के हालिया विस्तार से प्रमाणित होता है। उद्योग में प्रतिस्पर्धा के लिए वास्तविक खतरा भारी पाटन है, जिसने किसी भी अन्य नए प्रवेशकों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न की है; और मौजूदा व्यापारियों को उद्योग में आगे कोई निवेश करने से भी रोक रहा है।

ख. संबद्ध सामानों का प्रयोग मुख्य रूप से पॉलिएस्टर-आधारित कपड़ों और पीईटी बोतलों के निर्माण में किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क के संबंध में विस्तृत परिकलन पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो स्पष्ट रूप से

सिद्ध करते हैं कि लगभग 50 अमेरिकी डॉलर/एमटी के पाटनरोधी शुल्क का अंतिम प्रयोक्ता पर प्रभाव 0.3% या उससे कम होगा।

ग. मौखिक सुनवाई के दौरान, कुछ हितबद्ध पक्षकारों/प्रयोक्ता उद्योगों ने दावा किया कि यदि 30% शुल्क लगाया जाता है, तो पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर ("पीएसएफ") पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 15% की रेंज में होगा।

घ. आवेदक ने अनुरोध किया है कि मध्यवर्ती कच्चा माल होने के कारण, 4.28% का प्रभाव पीएसएफ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अगले चरण के उपभोक्ताओं पर आसानी से डाला जा सकता है। शुल्क केवल अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में लागत बन जाते हैं, जिन पर शुल्क का प्रभाव, निर्विवाद रूप से, 0.3% से अधिक नहीं होगा।

ङ. तत्काल निचले स्तर के उत्पाद और अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है।

च. गणना की परिकलन की भारी अशुद्धि के बावजूद, पॉलिएस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने "मेल्ट" पर प्रभाव का आकलन करने का सुझाव दिया है, जो एक ऐसा उत्पाद है जो बाजार में वाणिज्यिक रूप से बेचा भी नहीं जाता है। तदनुसार, आवेदक प्राधिकारी से इन अनुरोधों को अनदेखा करने का अनुरोध करता है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

136. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं से वर्तमान जाँच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिसमें अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का संभावित प्रभाव, विचाराधीन उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, माँग की कीमत-संवेदनशीलता, दीर्घकालिक संविदा आदि शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के कई प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है। प्रयोक्ता उद्योग ने अपने उत्तर में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला है:

क. बीकेलॉन, गार्डन सिल्क्स, डीएनएच, सनाथन और वेलनोउन उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद पर पहले से ही 18% जीएसटी लागू है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि कच्चे माल एमईजी और अंतिम उत्पाद, मानव निर्मित फाइबर के बीच कर अंतर है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से समस्या और बढ़ जाएगी।

ख. बीकेलॉन, गार्डन सिल्क्स, डीएनएच, सनाथन और वेलनोउन ने भी उल्लेख किया है कि उन्हें भारत में विचाराधीन उत्पाद उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी या भेदभावपूर्ण व्यवहार की जानकारी नहीं है।

ग. बीकेलॉन, गार्डन सिल्क्स, डीएनएच, सनाथन और वेलनोउन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शुल्क लगाए जाने की स्थिति में भारत में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति में कमी आ जाएगी।

घ. फिलाटेक्स ने कहा है कि टेक्सटाइल उद्योग में लाभ मार्जिन बहुत कम है और विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योगों का लाभ और भी कम हो जाएगा, जो ऐसे उद्योगों के होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

ङ. इंडोरामा सिंथेटिक्स ने उल्लेख किया है कि भारत में एमईजी की मांग उत्पादन क्षमता से अधिक है। इसलिए, अधिकांश उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के आयात पर निर्भर हैं। विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से टेक्सटाइल बाजार अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा।

च. बॉम्बे डाइंग का अनुरोध है कि भारतीय पीएसएफ उद्योग और निचले स्तर के मानव निर्मित फाइबर श्रृंखला पहले से ही चीन जैसे देशों से सस्ते आयात के कारण भारी कीमत निर्धारण दबाव का सामना कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने से पीएसएफ उत्पादकों की लागत बढ़ जाएगी।

छ. पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि एमईजी "पॉलिएस्टर मेल्ट" की लागत का 23.40% है। अत:, पाटनरोधी शुल्क लागू होने से निचले स्तर के उत्पाद पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

ज. भिलोसा इंडस्ट्रीज ने अनुरोध किया है कि मानव निर्मित फाइबर उद्योग कम लाभ मार्जिन पर काम करता है और शुल्क लागू होने की स्थिति में, कंपनी के पास निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर बढ़ी हुई लागत डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 30% शुल्क मार्जिन से पीएसएफ (एक मध्यवर्ती उत्पाद) पर 10-15% प्रभाव पड़ेगा।

137. घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर विचार करने के बाद अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिकलन भी दिया है, जिसका अनुमान उन्होंने 1% से कम लगाया है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत परिकलन पर भी विवाद किया है और अनुरोध किया है कि पीएसएफ एक मध्यवर्ती उत्पाद है। पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क का अधिकतम प्रभाव 4% होगा, जिसे अंतिम उपभोक्ताओं पर आसानी से डाला जा सकता है।

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सुधारात्मक उपाय लागू करने का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करना है। प्राधिकारी वास्तव में जानते हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। यद्यपि शुल्क लगाने से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन साथ ही यह देश के भीतर नए उत्पादकों के उद्भव या आगे के निवेश को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर बहाल करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को उचित और क्षतिरहित कीमतों पर संबद्ध सामानों तक पहुँच मिलती रहे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निरंतर और बेरोकटोक अनुचित व्यापार परिपाटियों का घरेलू उद्योग की कीमतों और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल क्षमता में भविष्य के निवेश हतोत्साहित होंगे, जिससे भारत की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता कमजोर होगी। इस प्रकार, व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने से न केवल घरेलू उद्योग को समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रयोक्ताओं का

जोखिम भी कम होगा, जिससे प्रयोक्ता उद्योग दीर्घावधि में कई स्रोतों से संबद्ध सामानों को अधिक प्रतिस्पर्धी रूप से खरीद सकेगा।

140. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया और अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग वर्तमान में विचाराधीन उत्पाद और अंतिम उत्पाद पर भिन्न जीएसटी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उन्होंने वस्त्र मंत्रालय के समक्ष इस बात को उजागर किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादकों द्वारा किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार या भेदभावपूर्ण व्यवहार का उल्लेख नहीं किया है।

141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वस्त्र उद्योग में लाभ मार्जिन बहुत कम है और शुल्क लगाने से उनकी लाभप्रदता प्रभावित होगी।

142. पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के संबंध में, प्राधिकारी ने भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत गणना की जाँच की है और उसे गलत पाया है। उदाहरण के लिए, पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना करते समय, प्रयोक्ता उद्योग ने एमईजी पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को तैयार उत्पाद के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया है, इस तथ्य की स्पष्ट रूप से अनदेखी करते हुए कि पाटनरोधी शुल्क के कारण एमईजी की कीमतों में वृद्धि केवल एमईजी के कारण होने वाली लागत को प्रभावित करेगी, जो पीएसएफ के कुल मूल्य का केवल 16% है। इसे नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	**गणना विधि**	**मूल्य**
एमईजी की कीमत (रु./एमटी)	ए	43,987
पीएसएफ की कीमत (रु./एमटी)	बी	***
पीएसएफ में एमईजी का %	सी	***
पाटनरोधी शुल्क (केवल उदाहरण) (*** डॉ./एमटी)	डी	***
पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क प्रभाव (जैसा कि प्रयोक्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है) की गणना पाटनरोधी शुल्क/तैयार उत्पाद के मूल्य के रूप में की जाती है।	ई=डी/बी	***

पीएसएफ में एमईजी लागत (रु./एमटी)	एफ=सी*बी	***
एमईजी लागत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव (रु./एमटी)	जी= एफ * (डी/ए)	***
पीएसएफ पर प्रभाव	I = जी/बी	3.6%

143. इस प्रकार, एक मध्यवर्ती उत्पाद, पीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव केवल 3.6% हो सकता है। यह नोट किया जाता है कि यदि शुल्क लगाया जाता है, तो इसका प्रभाव काफी नहीं होगा। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने यह तर्क नहीं दिया है कि वे इस लागत को अंतिम उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकते। इसके अलावा, किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विवरण नहीं दिया है। और न ही पीएसएफ जैसे तात्कालिक निचले स्तर के उत्पादों और पॉलिएस्टर मेल्ट जैसे मध्यवर्ती उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में गणना प्रदान की है। हालाँकि, किसी भी प्रयोक्ता ने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विवरण नहीं दिया है।

144. दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने विभिन्न अंतिम उपभोक्ता उत्पादों, अर्थात् पीईटी बोतलों और परिधानों (पुरुषों की शर्ट और महिलाओं की साड़ियों) पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना प्रस्तुत की है। इसे नीचे दर्शाया गया है:

अंतिम उत्पाद		**पीईटी आधारित अंतिम उत्पाद**			**यार्न आधारित अंतिम उत्पाद**	
विवरण	**यूओएम**	**पेय जल**	**कार्बोनेटेड पेय**	**यूओएम**	**पुरुषों की शर्ट**	**साड़ी**
मात्रा/ लंबाई	एमएल	1000	750	m	2.5	6
खुदरा मूल्य	रु.	20	40	रु.	350	300
पॉलिएस्टर जीएसएम	जीएम/एम	एनए	एनए	जीएम/एम	110	90
वजन	जीएम	18	25	जीएम	275	420
एमईजी मानक	किग्रा./किग्रा.	0.35	0.35	किग्रा./किग्रा.	0.35	0.35
एमईजी कीमत	रु./किग्रा.	44.00	44.00	रु./किग्रा.	44.00	44.00
अंतिम उत्पाद में एमईजी	जीएम	6.3	8.75	जीएम	96.25	147
अंतिम उत्पाद में एमईजी मूल्य	रु.	0.28	0.39	रु.	4.24	6.47

अंतिम उत्पाद में एमईजी %	**%**	**1.4%**	**1.0%**	**%**	**1.2%**	**2.2%**
एमईजी पाटनरोधी शुल्क दर	डॉ./एमटी	***	***	डॉ./एमटी	***	***
एमईजी पाटनरोधी शुल्क दर	रु./कि.ग्रा.	***	***	रु./कि.ग्रा.	***	***
एमईजी पाटनरोधी शुल्क प्रभाव	रु.	0.06	0.09	रु.	0.95	1.45
अंतिम उत्पाद कीमत का प्रभाव %	**%**	**0.31%**	**0.22%**	**%**	**0.27%**	**0.48%**

145. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद की कीमत पर 1% से भी कम प्रभाव पड़ेगा, जिसे वह आसानी से अंतिम उपभोक्ताओं पर डाल सकता है।

146. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी टिप्पणी की है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में आरआईएल का एकाधिकार हो जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरआईएल के अलावा, भारत में एमईजी के दो अन्य उत्पादक, अर्थात आईओसीएल और आईजीएल हैं। आईओसीएल ने हाल ही में अपने पानीपत संयंत्र में एमईजी का विस्तार किया है और पारादीप कॉम्प्लेक्स में नए एमईजी संयंत्र का भी प्रचालन किया है। इसके अलावा, प्रयोक्ता उद्योग की प्रतिक्रिया के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय प्रयोक्ताओं ने आरआईएल और आईओसीएल दोनों से बड़ी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद खरीदा है।

147. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि वे चीन से निचले स्तर के उत्पादों के सस्ते आयात के कारण पहले से ही दबाव में हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से पीईटी रेजिन, जो एक निचले स्तर के उत्पाद है, का आयात पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन है। इसके अतिरिक्त, यदि अन्य निचले स्तर के उत्पादों का आयात भारत

में पाटन किया जा रहा है, तो वे उचित समाधान के लिए इस प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

148. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि संबद्ध सामानों पर क्यूसीओ लगाए जाने के कारण, भारतीय बाजार तक पहुँच प्रतिबंधित हो गई है, जिससे भारत में एमईजी की आपूर्ति सीमित हो गई है, जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से और भी बढ़ जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्यूसीओ एक नियामक उपाय है, जिसका उद्देश्य आयात और घरेलू उत्पादन एवं बिक्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, प्रयोक्ता उद्योग के हितों को बढ़ावा देना है और यह संबद्ध देशों या अन्यत्र से आयात को नहीं रोकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रतिभागी निर्यातक ने यह दावा नहीं किया है कि उन्हें अपेक्षित प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ है।

149. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की माँग और आपूर्ति में काफी अंतर मौजूद है। जैसा कि ऊपर दिए गए खंडों में जांच की गई है, जांच की अवधि के अंत में आईओसीएल की नई क्षमता के चालू होने के बाद, प्राधिकारी ने पाया है कि बढ़ती भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों के आयात पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि इससे केवल भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए कीमतों में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे सामानों का गैर-संबद्ध देशों से भी आयात किया जा सकता है, जिससे भारतीय एमईजी बाजार और अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

ठ. <u>प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ</u>

ठ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

150. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

i. प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद की अवधि सहित संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान आरआईएल द्वारा किए गए आयातों का विश्लेषण नहीं किया है, तथा क्षति निर्धारण पर ऐसे आयातों के पूर्ण प्रभाव की उपेक्षा की है।

ii. आईजीएल के आंकड़ों पर भरोसा करना गलत है क्योंकि उसने लागत या क्षति के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड ने ट्रेड

नोटिस संख्या 13/2018 और 14/2018 के अनुसार जानकारी दाखिल नहीं की है।

iii. प्राधिकरण के पास वर्तमान एंटी-डंपिंग आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

iv. कम शुल्क नियम के सिद्धांत के अनुसार प्राधिकरण को भारित औसत/व्यक्तिगत उत्पादक के डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से न्यूनतम शुल्क लगाना होगा।

v. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 46 (ए) में प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि उसने शर्क की उत्पादन लागत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने यह उल्लेख नहीं किया है कि अन्य उत्पादकों द्वारा बताई गई लागत को स्वीकार किया गया है या नहीं।

vi. प्राधिकरण ने प्रतिवादियों के वास्तविक आंकड़ों की अनदेखी की है, जबकि ऐसे आंकड़े प्रतिवादियों के रिकार्ड से मेल खाते हैं तथा आवश्यक सिस्टम डंप के माध्यम से सत्यापित किए गए हैं।

vii. प्राधिकरण ने बिना कोई औचित्य बताए उत्तरदाताओं के वास्तविक आंकड़ों को अघोषित समायोजित आंकड़ों से बदल दिया है।

viii. इक्वेट और टीकेओसी की उत्पादन लागत में क्रमशः *** % और *** % की वृद्धि हुई है। उसी उत्पाद और उसी कंपनी के लिए, प्राधिकारी ने पिछली जाँच में कोई समायोजन नहीं किया था। दोनों जाँचों में कोई अंतर न होने के कारण, प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत को स्वीकार करना चाहिए था।

ix. प्राधिकरण ने प्रतिवादियों के समक्ष आवश्यक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है, जैसा कि एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत अपेक्षित है और यह रूस - वाणिज्यिक वाहन मामले में पैनल के निर्णय के विपरीत है। एसओपी के मैनुअल में कार्यप्रणाली सहित सामान्य मूल्य का विस्तृत खुलासा अपेक्षित है।

x. एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2.2 के अनुसार, प्राधिकरण को निर्यातकों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एसजीए और लाभ मार्जिन की गणना करनी होगी। प्राधिकरण ने निर्यातकों की वास्तविक लागतों में कुछ अघोषित समायोजन किए हैं और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च

न्यायालय और न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

xi. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एसजीए और लाभ कंपनी के अभिलेखों में रखे गए वास्तविक आंकड़ों से कहीं अधिक हैं। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपनाया गया एसजीए और लाभ घरेलू बाजार में समान सामान्य श्रेणी के उत्पादों के उत्पादकों द्वारा सामान्यतः प्राप्त लाभ से अधिक है या नहीं।

xii. प्राधिकरण को अपनी प्रथा के अनुसार निर्यातकों के सामान्य मूल्य की गणना के लिए 5% लाभ मार्जिन अपनाना चाहिए।

xiii. प्राधिकरण ने पेट्रोकेमिया, सऊदी कायान और यूनाइटेड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु एसजीए लागत को दो बार जोड़ा है।

xiv. प्राधिकरण को व्यापारी के लाभ मार्जिन को समायोजित करना चाहिए तथा निर्यात मूल्य में अप्रत्यक्ष एसजीए को अवश्य जोड़ा जाना चाहिए।

xv. चीन - एचपी-एसएसएसटी (ईयू) मामले में अपीलीय निकाय ने माना कि प्राधिकरण के लिए केवल उन आंकड़ों का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है जो इसकी गणना का आधार बनते हैं, बल्कि उसे आंकड़ों का खुलासा करना होगा।

xvi. अनुच्छेद 2.2.1.1, प्राधिकारी को उत्पादन लागत की गणना के लिए निर्यातक के अभिलेखों का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है, यदि ऐसी जानकारी अनुच्छेद में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है। वर्तमान मामले में, SABIC द्वारा निर्यातकों को प्रदान की गई जानकारी ऐसी शर्तों को पूरा करती है और इसलिए, प्राधिकारी को ऐसी जानकारी पर भरोसा करना चाहिए था, जब तक कि उन्हें ऐसी जानकारी को नज़रअंदाज़ करने के लिए कोई ठोस कारण न मिले।

xvii. प्राधिकरण को उत्पादन लागत की गणना करते समय इन्वेंट्री समायोजन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे समायोजनों में अन्य समायोजन शामिल होते हैं जैसे कि ***

xviii. प्राधिकरण आईओसीएल सहित अन्य उत्पादकों से आंकड़े मांगने में विफल रहा है और इस प्रकार, प्राधिकरण ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

आईओसीएल के आंकड़ों और प्रतिक्रिया को शामिल न करने से क्षति और कारण विश्लेषण की निष्पक्षता कमज़ोर होती है।

xix. उपयोगकर्ता उद्योग का मानना है कि आईओसीएल पीयूसी पर मुनाफ़ा कमा रहा है। तदनुसार, उत्तरदाताओं का मानना है कि बाजार में आईओसीएल का प्रदर्शन आरआईएल के क्षति दावों के विपरीत है।

xx. वित्त वर्ष 2021-22 से पीयूसी की निर्यात बिक्री में भारी गिरावट आई है, जबकि 2020-21 से वैश्विक स्तर पर पीयूसी की समग्र मांग बढ़ रही है, जिससे आरआईएल के आर्थिक मानदंड नकारात्मक हो रहे हैं।

xxi. आईओसीएल के हालिया क्षमता विस्तार के बावजूद, आरआईएल की बाजार हिस्सेदारी 75-90% है। केवल आरआईएल के प्रदर्शन पर आधारित क्षति विश्लेषण को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।

xxii. यदि आयात क्षति का कारण होता, तो अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री भी घरेलू उद्योग की बिक्री के साथ-साथ कम हो जाती। हालाँकि, बिक्री के रुझानों में भिन्नता कथित डंपिंग और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

xxiii. आरआईएल ने जांच की अवधि के दौरान सऊदी अरब और सिंगापुर से 14,330 मीट्रिक टन का आयात किया तथा जांच की अवधि के बाद उसने सऊदी अरब और अमेरिका से 22,392 मीट्रिक टन एमईजी का आयात किया है।

xxiv. प्राधिकरण ने आयात की मात्रा में 19% की गिरावट को नगण्य माना है, जबकि उत्पादन में 16% की गिरावट को महत्वपूर्ण माना है।

xxv. आधार वर्ष के साथ प्राधिकरण की तुलना गलत है क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के साथ मेल खाता है जब मांग और आपूर्ति असामान्य रूप से कम थी।

xxvi. प्राधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि आयात की मात्रा में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है, जबकि अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयात क्षति का कारण नहीं है।

xxvii. मूल्य कटौती का आकलन सम्पूर्ण क्षति अवधि के लिए किया जाना चाहिए, न कि केवल जांच अवधि के लिए।

xxviii. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों पर निरंतर गिरावट का दबाव नहीं पड़ा है क्योंकि आयात कीमतें वास्तव में जांच अवधि में 100 से बढ़कर 113 हो गई हैं। जांच अवधि में आयात की मात्रा 2022-23 की तुलना में बढ़ी नहीं है, बल्कि घटी है।

xxix. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ईथेन की कीमतों के रुझान का अनुसरण किया गया है। तदनुसार, लाभप्रदता में गिरावट सहयोगी कंपनियों से खरीदे गए ईथेन की कीमतों में वृद्धि के कारण है।

xxx. 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कुवैत से आयात की कीमतें बढ़ने पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और बिगड़ गई। अगर आयात वास्तव में इसके लिए ज़िम्मेदार होता, तो 2021-22 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार होता।

xxxi. इसके अलावा, जांच अवधि में आयात कीमतों में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, जो आगे यह स्थापित करता है कि कथित क्षति और आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

xxxii. अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क में गिरावट के कारण भारतीय कीमतों में गिरावट के संबंध में, प्राधिकरण ने रसायनों में कमोडिटी चक्र की अनदेखी की है।

xxxiii. बाजार हिस्सेदारी के संबंध में, प्राधिकारी ने अन्य भारतीय उत्पादकों के प्रभाव को खारिज कर दिया है और माना है कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण अपनी हिस्सेदारी खो दी है। आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों, दोनों की गैर-कैप्टिव बिक्री 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में बढ़ी है (84 से 156 तक), जो आयातों द्वारा अधिग्रहण के बजाय भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के भीतर पुनर्वितरण को दर्शाती है। इस तत्व की अनदेखी करना और आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में पूरी गिरावट के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार ठहराना विश्लेषणात्मक रूप से अनुचित है।

xxxiv. प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि लाभप्रदता में गिरावट केवल इसलिए आई क्योंकि घरेलू उद्योग की लागत के अनुरूप भूमि मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। यह तर्क घरेलू उद्योग की अपनी लागत वृद्धि का बोझ प्रभावी रूप से आयात पर डाल देता है।

xxxv. घरेलू उद्योग ने प्रतिवादी के इस दावे का खंडन नहीं किया है कि सहयोगी कंपनियों से ईथेन की खरीद पूरी तरह से उचित नहीं है और कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रतीत होती है। केवल यह कहना कि ईथेन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क पर आधारित हैं, पर्याप्त नहीं है।

xxxvi. घरेलू उद्योग द्वारा अपने सहयोगी से इथेन की खरीद मूल्य की जांच की जा सकती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह उचित सीमा के भीतर है।

xxxvii. प्राधिकरण द्वारा आरआईएल के निवेशक प्रस्तुतीकरणों को खारिज करना अनुचित है। ये प्रस्तुतीकरण कोई सामान्य बयान नहीं हैं, बल्कि सख्त कॉर्पोरेट और प्रतिभूति कानून दायित्वों के तहत शेयरधारकों को दिए गए आधिकारिक खुलासे हैं, और ये उद्योग की स्थितियों के बारे में कंपनी के सुविचारित आकलन को दर्शाते हैं।

xxxviii. कुवैत के निर्यातकों का उत्पादन 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में मात्र *** % बढ़ा और वे जांच अवधि में लगभग पूर्ण क्षमता उपयोग (अर्थात *** %) पर काम कर रहे थे।

xxxix. सीमित अधिशेष क्षमता का अस्तित्व अपने आप में खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; कुवैत और अन्य संबद्ध देशों के उत्पादक विश्व स्तर पर निर्यात करते हैं और उनके बाजार विविध हैं।

xl. यह निष्कर्ष कि इक्वेट समूह के उत्पादन का 53% भारत को निर्यात था, भ्रामक है। इन निर्यातों में व्यापारिक बिक्री शामिल है और ये भारतीय ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति संबंधों को दर्शाते हैं, न कि अधिशेष क्षमता के अचानक हस्तांतरण को। यह तथ्य कि जाँच अवधि में तीसरे देशों को निर्यात में मात्र *** % की गिरावट आई, भारत को निर्यात हस्तांतरण का संकेत नहीं देता; यह केवल वैश्विक व्यापार का प्रतिबिंब है।

xli. अगर कुवैत सचमुच भारत में अपनी अतिरिक्त क्षमता को बेचना चाहता होता, तो जाँच अवधि के दौरान आयात में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती थी। इसके बजाय, कुवैत से भारत को होने वाला निर्यात वास्तव में 2022-23 में *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन रह गया, जिससे प्राधिकरण के खतरे संबंधी निष्कर्ष का आधार ही कमजोर हो गया।

xlii. प्राधिकरण को एनआईपी निर्धारित करने के लिए कृत्रिम मूल्य के बजाय कैप्टिव इनपुट के हस्तांतरण मूल्य को अपनाना चाहिए।

xliii. आईओसीएल द्वारा अपनी वेबसाइट पर स्वीकार किया गया है कि उसका विस्तार मांग-आपूर्ति के अंतर को आंशिक रूप से ही पूरा करता है। आपूर्ति की समस्याएँ हैं और उपयोगकर्ता आयात पर निर्भर हैं और आयात करने को मजबूर हैं।

xliv. आरआईएल न केवल पीयूसी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि डाउनस्ट्रीम कपड़ा उद्योग का भी सबसे बड़ा निर्माता है। इस प्रकार, कच्चे माल और पीयूसी पर आरआईएल का महत्वपूर्ण नियंत्रण है। अन्य डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के साथ हितों का एक अंतर्निहित और सीधा टकराव है। एडीडी लगाने से आरआईएल के हितों को ही बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह अपने उत्पादन का लगभग 70% निजी उपभोग के लिए उपयोग करता है।

xlv. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से कपड़ा उद्योग पर बोझ पड़ेगा और राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं रोज़गार ख़तरे में पड़ जाएगा। एडीडी लगाने से आयातित एमईजी तक पहुँच में भारी कमी आएगी।

xlvi. प्राधिकरण ने कहा है कि एमईजी, पीएसएफ मूल्य का केवल लगभग 16% है और 3.6% प्रभाव दर्शाने वाली एक तालिका प्रस्तुत की है, लेकिन इन निष्कर्षों पर आधारित सटीक धारणाएँ और गणनाएँ अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। विशेष रूप से, एमईजी लागतों के आवंटन के लिए अपनाई गई पद्धति, पीएसएफ मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्य और लागू रूपांतरण मानदंड सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इससे संबंधित पक्षों को आंकड़ों की सत्यता पर सार्थक टिप्पणी करने या उनकी सत्यता की पुष्टि करने से रोका जा सकता है।

xlvii. एडीडी, जीएसटी अंतर और मौजूदा आयात शुल्कों का संचयी प्रभाव उपयोगकर्ता उद्योगों की लागत संरचना को और भी बदतर बना देगा। इस प्रणालीगत बोझ की अनदेखी प्राधिकरण के विश्लेषण को गलत साबित करती है।

xlviii. प्राधिकरण ने आरआईएल के एकाधिकार से संबंधित इस चिंता को इस आधार पर सिरे से खारिज कर दिया है कि आईओसीएल और आईजीएल जैसे अन्य उत्पादक मौजूद हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी क्षमता का विस्तार

किया है। प्राधिकरण को यह समझना होगा कि भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हितों के लिए एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना अपरिहार्य है।

ठ.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

151. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

क. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 26 में प्राधिकारी ने केवल यह टिप्पणी की है कि प्रत्येक जाँच उस विशेष जाँच के तथ्यों को ध्यान में रखकर की जानी है। तथापि, यह निर्विवाद है कि पिछली जाँच में संबद्ध देशों के निर्यातक पाटन करते पाए गए थे। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे यह निष्कर्ष निकालें कि संबद्ध देशों के निर्यातक 2020 से ही संबद्ध वस्तुओं की पाटन कर रहे हैं।

ख. घरेलू उद्योग पीटीए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बॉम्बे डाइंग, फिलाटेक्स इंडिया और इंडोरामा सिंथेटिक्स के उपयोगकर्ता प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने की अपनी मांग दोहराता है। उपयोगकर्ता प्रश्नावली का उत्तर आवेदक को केवल लिखित प्रस्तुतिकरण के चरण में ही वितरित किया गया था। तदनुसार, हम प्राधिकारी से ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार करने का अनुरोध करते हैं।

ग. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 33 में प्राधिकरण ने सऊदी अरब में पीएमएस के अस्तित्व से संबंधित अपने पिछले निष्कर्षों की पुष्टि की है। हालाँकि, प्राधिकरण ने नोट किया है कि रिकॉर्ड में इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि इस तरह की विकृति निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य के बीच तुलना को प्रभावित करती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने सऊदी अरब के उत्पादकों की उत्पादन लागत में पीएमएस के आरोपों के आधार पर कोई समायोजन नहीं किया।

घ. घरेलू उद्योग ऑस्ट्रेलिया में पैनल रिपोर्ट - *ए4 कॉपी पेपर को याद करता है* , जिसमें पैनल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए वस्तुओं के निर्माण में एक ही विकृत इनपुट का उपयोग किए जाने पर भी, पीएमएस निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्य के बीच मूल्य तुलना को प्रभावित नहीं करता है। इसके बजाय, प्राधिकरण को लाभप्रदता का बाजार-वार आकलन करना चाहिए था और

विभिन्न खंडों में कच्चे माल की विकृति के प्रभाव की जांच करनी चाहिए थी, इससे पहले कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कच्चे माल की विकृति प्रतिवादी उत्पादकों की मूल्य तुलना को प्रभावित नहीं करती है।

ङ. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 47 के आधार पर, घरेलू उद्योग यह समझता है कि प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उसी विकृत इनपुट मूल्य पर विचार किया है। यह स्वीकार करते हुए कि केएसए के बाजार में कच्चे माल की कीमत में विकृति मौजूद है, प्राधिकारी को पाटन मार्जिन की गणना हेतु निर्मित सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केएसए के भीतर विकृत एथिलीन और उपयोगिता कीमतों को अविकृत कीमतों से प्रतिस्थापित करना चाहिए।

च. घरेलू उद्योग ने एसओके में पीएमएस के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं, और तदनुसार, यह साबित करने का भार एसओके के निर्यातकों पर आ जाता है कि पीएमएस का अस्तित्व नहीं है। यह दोहराया जाता है कि कुवैत सरकार ने एक शाही आदेश जारी किया है जिससे इक्वेट समूह के दो निर्यातकों को महत्वपूर्ण फीडस्टॉक की खरीद काफी कम दरों पर करने की अनुमति मिल गई है। इसलिए, घरेलू उद्योग प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर में पैनल के निर्णय के अनुरूप, एसओके में भी पीएमएस के अस्तित्व को मान्यता दे और एसओके में उत्पादकों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य को अविकृत इनपुट मूल्य को दर्शाने के लिए समायोजित करे।

छ. प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे हैं कि इक्वेट ग्रुप और एसएबीआईसी ग्रुप के लिए प्रमुख कच्चा माल आपूर्तिकर्ता एक संबंधित इकाई है और इसलिए, पीएमएस की अनुपस्थिति में भी, प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए थी कि क्या ऐसे कच्चे माल की कीमतें उचित सीमा से अधिक हैं। घरेलू उद्योग समझता है कि इन संबंधित आपूर्तिकर्ताओं में से किसी को भी ऐसी जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं कहा गया है। तदनुसार, प्राधिकारी को निर्मित सामान्य मूल्य की गणना के लिए प्रमुख कच्चे माल, विशेष रूप से एथिलीन, के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर विचार करना चाहिए।

ज. प्राधिकारी को आयातों में पूर्ण और सापेक्ष वृद्धि, संबद्ध देशों से सकारात्मक और महत्वपूर्ण पाटन, घरेलू उद्योग के परिमाणात्मक और वित्तीय मापदंडों में गिरावट के सकारात्मक साक्ष्य मिले हैं, घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण है और संबद्ध देशों में निर्यातक संरचनात्मक रूप से

निर्यातोन्मुख हैं, तथा संबद्ध देशों में 95% से अधिक घरेलू उत्पादन घरेलू खपत से अधिक है।

झ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच करते समय, प्राधिकरण ने *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी एवं अन्य* (अंतिम आदेश संख्या 51370/2023) में माननीय सीईएसटीएटी के आदेश की अनदेखी की है, जिसमें *रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम यूओआई* [2006 (202) ईएलटी 23 (एससी)] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया था कि क्षति के आकलन के लिए प्राधिकरण को कैप्टिव इनपुट के बाजार मूल्य पर विचार करना चाहिए न कि आंतरिक हस्तांतरण मूल्यों पर।

ञ. सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय क्षति मूल्यांकन के साथ-साथ क्षति की क्षति के निर्धारण से संबंधित था। क्षति की क्षति के निर्धारण के लिए, ए.डी. नियम, 1995 में अनुबंध-III को बाद में जोड़ने से, ए.डी. नियम, 1995 के अनुबंध-II की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या, जो क्षति परीक्षण को नियंत्रित करती है, कमजोर या रद्द नहीं होती है।

ट. घरेलू उद्योग की स्वीकृत एनआईपी, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई एनआईपी से काफी कम है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एनआईपी में कई अनुचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्राधिकरण को घरेलू उद्योग की एनआईपी की पुनः जाँच करनी चाहिए।

ठ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

152. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों की जाँच की है और नोट किया है कि कई प्रस्तुतियाँ उन मुद्दों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जाँच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दे और जिन्हें साक्ष्य सहित प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, उनकी जाँच नीचे की गई है।

153. क्षति अवधि के दौरान आरआईएल द्वारा किए गए आयातों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरआईएल ने संबद्ध वस्तुओं का आयात केवल जांच अवधि के

दौरान ही किया है और ऐसे आयात उसके कुल उत्पादन और बिक्री के 1% से भी कम हैं, जो कि नगण्य मात्रा है । आरआईएल ने क्षति अवधि के पिछले वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया था।

154. आईजीएल के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि समर्थकों को व्यापार सूचना 04/2021 के नोट 2 के अनुसार स्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। प्राधिकरण ने नोट किया है कि आईजीएल ने वास्तव में प्रारूप के अनुसार आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, आईओसीएल ने भी प्राधिकरण के समक्ष एक समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था, हालाँकि, उसने व्यापार सूचना के अनुसार आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

155. वर्तमान आवेदन पर विचार करने के क्षेत्राधिकार के अभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामला प्राधिकारी को वापस भेज दिया था, जिसके बाद प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 14(क) के अनुसार जाँच समाप्त करने का अनुरोध प्राप्त होने पर जाँच समाप्त कर दी। किसी भी स्थिति में, वर्तमान जाँच एक भिन्न विषयगत देश मिश्रण के विरुद्ध है और एक भिन्न क्षति अवधि से संबंधित है। आवेदन का विधिवत दस्तावेजीकरण किया गया था और इसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच शुरू की।

156. भाग लेने वाले निर्यातकों ने दावा किया है कि उनकी उत्पादन लागत में मनमाने ढंग से संशोधन किया गया है और पीयूसी से संबंधित पिछली जाँच में ऐसा संशोधन नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने नोट किया है कि प्रत्येक जाँच विशिष्ट तथ्यों, प्रस्तुत किए गए निवेदनों और जाँच के दौरान प्रदान की गई जानकारी तथा प्रासंगिक सहायक साक्ष्यों के आधार पर की जाती है।

157. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि कई हितधारक पक्षों ने दावा किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन से संबंधित विस्तृत गणनाओं का खुलासा नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने अपनी सतत् कार्यप्रणाली के अनुसार आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया है।

158. सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी को इक्वेट ग्रुप के उत्तर में कई अशुद्धियाँ और कमियाँ मिलीं, जैसे कि पीयूसी के लिए बताई गई एथिलीन (कैप्टिव इनपुट) की लागत कंपनी

स्तर पर बताई गई एथिलीन की लागत (पीयूसी और एनपीयूसी) से काफी कम थी। अपने मूल उत्तर में, इक्वेट ग्रुप ने उप-उत्पाद क्रेडिट के लिए दोहरी कटौती का भी दावा किया था, जिसके लिए कोई उचित औचित्य नहीं दिया गया था। इसी प्रकार, भारत को निर्यात के लिए इक्वेट ग्रुप द्वारा बताई गई माल ढुलाई को कई बार संशोधित किया गया था। इसके अलावा, परिशिष्टों में इन्वेंट्री समायोजन के दावे को भी संशोधित किया गया था। इस प्रकार, सत्यापन के दौरान इक्वेट ग्रुप द्वारा पर्याप्त संशोधन किए गए थे, जिन्हें प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में ले लिया है।

159. प्राधिकरण ने इक्वेट ग्रुप द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पादन की लागत निर्धारित की है, जहां तक उसे सत्यापित किया जा सकता है। यह नोट किया गया था कि इक्वेट और टीकेओसी दोनों ने अपने संबंधित पक्ष, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ("केपीसी") से कैप्टिव इनपुट एथिलीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल (ईथेन) खरीदा था, हालांकि, मूल प्रतिक्रिया में प्रस्तुत परिशिष्ट 10 में उनके द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा यह भी नोट किया गया कि इक्वेट ग्रुप में दोनों उत्पादकों द्वारा बताई गई ईथेन खरीद मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर था। इक्वेट ग्रुप ने अपने दावा किए गए खरीद मूल्य को प्रमाणित करने के लिए केपीसी के साथ फीडस्टॉक आपूर्ति समझौतों की प्रति प्रदान करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि " *उक्त समझौते में बहुत ही गोपनीय और व्यावसायिक रूप से बेहद संवेदनशील जानकारी है, और इस तरह, इसे रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है* " / प्राधिकरण नोट करता है कि एडी नियम, 1995 के नियम 7 के तहत

160. इसके अतिरिक्त, इक्वेट ग्रुप कुछ लागतों का आवंटन न करने का पर्याप्त औचित्य प्रदान करने में विफल रहा, जिन्हें पीयूसी को आवंटित किया जाना चाहिए था। इक्वेट ग्रुप द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत जानकारी से भिन्न पाया गया। तदनुसार, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए, इस जाँच के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ऐसी लागत आवंटित की है।

161. सऊदी अरब के निर्यातकों द्वारा उत्पादन लागत की गणना करते समय इन्वेंट्री समायोजनों पर विचार न किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए निवेदनों के संदर्भ में, क्योंकि ऐसे समायोजनों में ***, प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसे समायोजनों को उत्पादन लागत की गणना में शामिल किया गया है, जहाँ उनकी पुष्टि की गई है। तदनुसार, प्राधिकरण ने अपनी सतत् प्रथा के अनुसार उत्पादन लागत की गणना की है।

162. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए एसजीए और लाभ से संबंधित दावों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि यह एडी नियम, 1995 के अनुबंध 1 के पैरा 4 के अनुसार व्यक्तिगत निर्यातकों की उत्पादन और बिक्री की सूचना की सत्यापित लागत पर आधारित था। प्राधिकरण आगे स्पष्ट करता है कि पेट्रोकेमिया, सऊदी कायान और यूनाइटेड के मामले में एसजीए लागत को दो बार नहीं जोड़ा गया था।

163. व्यापारी के लाभ मार्जिन और अप्रत्यक्ष एसजीए को एसएबीआईसी समूह के निर्यात मूल्य में समायोजित करने के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि कारखाना-बाहर निर्यात मूल्य प्रत्येक उत्पादक के स्तर पर निर्धारित किया गया है।

164. आईओसीएल की गैर-भागीदारी और आईओसीएल के आंकड़ों की गैर-जांच के कारण प्राधिकरण की जांच की निष्पक्षता पर विवाद करने वाले पीटीए यूजर इंडस्ट्रीज और मित्सुबिशी के दावों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उसने आईओसीएल सहित सभी घरेलू उत्पादकों से जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, प्राधिकरण को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप के अनुसार आईओसीएल से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तदनुसार, प्राधिकरण ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर क्षति की जांच की है।

165. इक्वेट ग्रुप ने आरोप लगाया है कि आरआईएल ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इसकी पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान जाँच एक मूल जाँच होने के कारण, प्राधिकारी जांच की अवधि के बाद के घटनाक्रमों की जाँच करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

166. जांच अवधि के दौरान आयात मात्रा में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट के संबंध में, प्राधिकारी प्रकटीकरण विवरण के पैरा 96 में की गई अपनी जांच का स्मरण करते हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से पाया गया था कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की गैर-कैप्टिव बिक्री में वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, जबकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आई, घरेलू उद्योग और एमईजी के अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई।

167. भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के भीतर बाजार हिस्सेदारी के पुनर्वितरण से संबंधित इक्वेट ग्रुप के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि भारतीय एमईजी

उद्योग की कुल बिक्री में वृद्धि के बावजूद, प्राधिकरण ने नोट किया कि समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी भी 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में घटी है।

168. इक्वेट ग्रुप ने प्रस्तुत किया है कि कुवैत से आयातित वस्तुओं के पहुँच मूल्य में वृद्धि के बावजूद, 2021-22 के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट आई है। इस संबंध में, प्राधिकारी अंतिम निष्कर्षों के पैरा 102-103 में अपने निष्कर्षों को याद करते हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि 2021-22 में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के पहुँच मूल्य में वृद्धि हुई, परन्तु यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

169. एसएबीआईसी समूह ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया है कि उसके संबंधित आपूर्तिकर्ता से एथेन की खरीदारी सीमा-पार नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उसने क्षति अवधि के लिए घरेलू उद्योग से तिमाही-वार चालान और संबंधित बेंचमार्क प्राप्त किए हैं और उनकी जाँच की है। इनकी जाँच करने पर, प्राधिकरण ने पाया कि ये लेन-देन सीमा-पार थे।

170. 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में वास्तव में सुधार हुआ है। हालाँकि, यह सुधार QCO लागू होने के कारण हुआ है।

171. पीटीए यूजर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि उसका मानना है कि आईओसीएल मुनाफा कमा रही है, जो घरेलू उद्योग के नुकसान के दावों के विपरीत है। पीटीए यूजर इंडस्ट्रीज ने आईओसीएल की लाभप्रदता के स्तर से संबंधित कोई भी आँकड़ा रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण ने सभी भारतीय उत्पादकों के आँकड़े माँगे थे। हालाँकि, आईओसीएल ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराया। तदनुसार, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान जाँच की है।

172. संपूर्ण क्षति अवधि के लिए मूल्य कटौती के निर्धारण के संदर्भ में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्य कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए किया जाना है।

173. इक्वेट ग्रुप ने दावा किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उसके उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है और सीमित अधिशेष क्षमता के अस्तित्व को वास्तविक क्षति के खतरे के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इक्वेट ग्रुप ने आगे

तर्क दिया है कि भारत में उत्पादन के अचानक विचलन का कोई साक्ष्य नहीं है और कुवैत और अन्य देशों के उत्पादक वैश्विक स्तर पर निर्यात करते हैं और उनके बाजार विविध हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वास्तविक क्षति के खतरे के अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए संबद्ध देशों का संचयी मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उन्होंने केवल संबद्ध देशों के निर्यातकों की संरचनात्मक निर्यात निर्भरता को इंगित किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत हैं कि इक्वेट ग्रुप द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात बिक्री में वास्तव में इक्वेट ग्रुप द्वारा की गई व्यापारिक बिक्री शामिल है, एक तथ्य जो अंतिम जांच परिणाम के पैरा 114 में दर्ज किया गया था।

174. एसएबीआईसी समूह ने दलील दी है कि एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग के बहीखातों के आधार पर की जानी चाहिए, न कि कैप्टिव इनपुट की काल्पनिक कीमतों के आधार पर। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी आरोप लगाया है कि प्राधिकारी ने उसकी क्षति-रहित कीमत में अनुचित समायोजन किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग के अभिलेखों के आधार पर, पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।

175. इक्वेट ग्रुप ने एंटी-डंपिंग शुल्कों के कारण पीएसएफ पर 3.6% प्रभाव को चुनौती दी है और दावा किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एमईजी, पीएसएफ मूल्य का 16% कैसे बनता है। प्राधिकरण अंतिम निष्कर्षों के पैरा 137 को याद करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदान की गई गणना की जाँच की गई है। एंटी-डंपिंग शुल्कों के प्रभाव के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार की गई सभी धारणाएँ भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदान की गई धारणाओं पर आधारित हैं। एमईजी के आगमन मूल्य पर डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार विचार किया गया है।

176. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीयूसी के किसी भी उपयोगकर्ता ने प्रकटीकरण विवरण में अंतिम उपयोगकर्ता पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव के बारे में कोई विवाद नहीं किया है या कोई और गणना प्रदान नहीं की है।

177. इक्वेट ग्रुप ने टिप्पणी की है कि आयात शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क के साथ मौजूदा जीएसटी अंतर उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए लागत संरचना को और खराब कर देगा। प्राधिकरण ने नोट किया है कि उलटे जीएसटी ढांचे से संबंधित मुद्दा प्राधिकरण के निर्धारण के दायरे में नहीं आता है। बहरहाल, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में इस तरह

के उलटे शुल्क ढांचे के मुद्दे को हल करने के लिए उचित जीएसटी दर संशोधन किए गए हैं।

ड. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

178. प्रस्तुत किए गए निवेदनों, हितबद्ध पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई पुष्ट सूचना तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफों में दर्ज किया गया है और जिनकी जांच की गई है, तथा पाटन के निर्धारण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

i. पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार, संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुएँ और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ एक दूसरे के समान वस्तुएँ हैं।

ii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पात्र घरेलू उत्पादन का 70-80% हिस्सा है, और तदनुसार, आवेदक एडी नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है और आवेदन एडी नियम, 1995 के नियम 5 (3) के तहत स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

iii. आवेदन में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाएं तथा एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 5(2) के अनुसार आवश्यक साक्ष्य शामिल थे, ताकि एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग को डंपिंग और भौतिक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराया जा सके।

iv. गोपनीयता से संबंधित दावों को जहां भी आवश्यक था, स्वीकार कर लिया गया और जहां गोपनीयता के ऐसे दावे अत्यधिक पाए गए, वहां हितबद्ध पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे उन्हें प्रकट करें या पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7 के अनुसार उनका उपयुक्त अगोपनीय सारांश प्रदान करें। जहां हितबद्ध पक्षों ने सूचना प्रदान नहीं की या सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया, वहां प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया है।

v. **पाटन मार्जिन**: संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा सामान्य मूल्य/निर्मित सामान्य मूल्य (जहां लागू हो) के आधार पर निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण निर्धारित किया गया।

vi. **मात्रा प्रभाव:** विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर पाए गए। घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के पैरा (ii) के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है, यह पाया गया कि ऐसे आयातों में भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। जांच अवधि में विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात में 200% की वृद्धि हुई है।

vii. **मूल्य प्रभाव:** ऐसे पाटित आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह पाया गया कि तीनों संबद्ध देशों से मूल्य कटौती सकारात्मक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि ऐसे पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे।

viii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इस तरह के डंपिंग के प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

क. **उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाज़ार हिस्सेदारी:** घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जबकि क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। गैर-कैप्टिव बिक्री में वित्त वर्ष 2022-23 तक गिरावट आई है, जिसमें QCO लागू होने के कारण आयात की मात्रा में कमी आई है, जो कि जांच अवधि में मामूली वृद्धि के साथ है। हालाँकि, क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा दोगुनी हो गई है।

ख. **बाजार हिस्सेदारी: क्षति अवधि के दौरान** घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बाजार हिस्सेदारी में *** % की गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयातित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में *** % की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्ज़ा कर लिया है। भारतीय उद्योग, अर्थात् घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी क्षति अवधि के दौरान सामूहिक रूप से बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

ग. **बिक्री लागत, विक्रय मूल्य, लाभप्रदता और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल:** घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में 2022-23 और 2021-22 की तुलना में जाँच अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में मामूली सुधार हुआ है, हालाँकि, 2020-21 और

2021-22 की तुलना में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान बिक्री लागत पर *** % का लाभ अर्जित किया है।

घ. **इन्वेंटरी:** जांच अवधि में इन्वेंटरी में वृद्धि हुई है।

ङ. **कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता और मजदूरी:** घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता में गिरावट आई है और जांच अवधि में यह अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है।

च. **वृद्धि**: आधार वर्ष से तुलना करने पर यह पाया गया कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभ और आरओसीई में गिरावट आई है तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

ix. **भौतिक क्षति का खतरा**: संबद्ध देशों के निर्यातक संरचनात्मक रूप से निर्यातोन्मुख हैं। तीसरे देशों में स्थिर माँग के कारण, यह संभावना है कि आयात भारत की ओर मोड़ दिया जाएगा।

x. **क्षति मार्जिन:** पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य और पाटनरोधी नियम के नियम 17(3)(बी) के अंतर्गत अपेक्षित विषयगत देशों से विषयगत आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना करने पर, भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक पाया गया।

xi. **कारणात्मक संबंध:** घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण भौतिक क्षति हुई है और इस क्षति का कोई अन्य ज्ञात कारण नहीं पाया गया है। आधार वर्ष और 2021-22 की तुलना में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति ने आवेदक को गैर-लाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया, जिससे घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xii. **भारतीय उद्योग के मुद्दे:** किसी भी इच्छुक पक्ष ने अंतिम उपयोगकर्ता शुल्क प्रभाव गणना पर विवाद नहीं किया है, जो *** % से कम है। एक जीवंत भारतीय घरेलू उद्योग सहित कई आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से उपयोगकर्ता के जोखिम को कम करती है और इस प्रकार उपयोगकर्ता उद्योग को दीर्घावधि में कई स्रोतों से अधिक प्रतिस्पर्धी रूप से संबंधित वस्तुओं की खरीद करने में सक्षम बनाती है।

179. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

180. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	**शीर्षक**	**विवरण**	**मूल देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि ($ / एमटी)**
1	2	3	4	5	6	7
1	2905 31 00	मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल	कुवैत राज्य	कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी के.एस.सी.सी	102

2	-वही	-वही	कुवैत राज्य	कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	कुवैत ओलेफिन्स कंपनी के.एस.सी.सी	102
3	-वही	-वही	कुवैत राज्य	कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से 2 के अलावा कोई भी उत्पादक	165
4	-वही	-वही	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	कुवैत राज्य	कोई	165
5	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
6	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
7	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
8	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	जुबैल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
9	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी	118

10	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
11	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	रबीग रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	118
12	-वही	-वही	सऊदी अरब के राज्य	सऊदी अरब और कुवैत राज्य सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 5 से 11 के अलावा कोई भी उत्पादक	173
13	-वही	-वही	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	सऊदी अरब के राज्य	कोई	173
14	-वही	-वही	सिंगापुर गणराज्य	सिंगापुर गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई	137
15	-वही	-वही	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	सिंगापुर गणराज्य	कोई	137

ढ. आगे की प्रक्रिया

181. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी